जंगलों में आग

उत्तराखंड प्रभावित

जंगलों में आग से उत्तराखंड का संवेदनशील परिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हुआ है और नैनीताल इसका केवल एक उदाहरण है। ऐतिहासिक रूप से भारत के अन्य पहाड़ी राज्यों की तुलना में उत्तराखंड जंगलों में आग की विभीषिका से ज्यादा प्रभावित होता है। अपने मनोहारी सौंदर्य तथा हरे-भरे परिवेश के लिए लोकप्रिय यह राज्य एक बार फिर जंगलों में आग की समस्या झेल रहा है। स्थिति की गंभीरता इस बात से स्पष्ट होती है कि जनवरी से जंगलों में आग की 500 से अधिक घटनायें सामने आई हैं और पिछले चौबीस घंटो में लगभग हर घंटे आग की खबर आई है। नवीनतम घटना नैनीताल के बसे क्षेत्रों के बहुत निकट हुई है। इसमें 108 एकड़ वन भूमि नष्ट हो गई है तथा इसने निवासियों और अधिकारियों में भय पैदा कर दिया है। स्थिति खराब होने पर सेना और भारतीय वायुसेना को नियंत्रण प्रयासों में सहायता के लिए लगाया गया है। जंगलों में लगने वाली ऐसी आग अक्सर लोगों द्वारा सूखे पेड़ों-झाड़ियों को हटाने में होने वाली गलतियों या सूखी वनस्पतियों में प्राकृतिक रगड़ से पैदा हो जाती है और तेज हवाओं से फैलती है। इससे संवेदनशील परिस्थितिकी तंत्र को भारी खतरा पैदा होता है। आग बुझाने और उसे फैलने से रोकने के प्रयासों के बावजूद वह मानव बस्तियों के निकट पहुंच गई है। भारतीय वायुसेना के हेलीकाप्टर पानी छिड़क कर आग बुझाने के प्रयास कर रहे हैं और इनसे दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंचने में सहायता मिली है। इसके साथ ही सेना के जवान जमीन पर आग बुझाने तथा इसे और फैलने से रोकने के प्रयास कर रहे हैं। इस चुनौती का सकारात्मक पक्ष यह है कि जंगलों की आग बुझाने में अधिकारियों के साथ सभी लोग भाग ले रहे हैं।

आग और उससे पैदा दमघोंटू धुंए के बीच लोगों में सामुदायिक भावना पैदा हुई है और वे आपदा से निपटने का प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय लोग, स्वयंसेवकों तथा एनजीओ के साथ एकजुट होकर आग बुझाने के प्रयासों में सहायता करने के साथ इससे प्रभावित लोगों की भी सहायता कर रहे हैं।

भोजन व शरणस्थल प्रदान करने के साथ पीड़ित लोगों को बाहर निकालने में हो रहे सामूहिक प्रयास विपरीत स्थितियों में समुदाय की सामूहिक प्रतिक्रिया का प्रदर्शन है। लेकिन जंगलों की आग के गंभीर पर्यावरणीय प्रभाव होते हैं। बहुमूल्य वनस्पतियों और जीवों के नष्ट होने के साथ ही इनसे वातावरण में खतरनाक प्रदूषक भी फैलते हैं। इससे भविष्य में जंगलों में आग लगने की घटनायें रोकने की तात्कालिक आवश्यकता उजागर होती है। इसके लिए वन प्रबंधन व्यवहारों को मजबूत करने, शीघ्र चेतावनी व्यवस्थाओं का प्रयोग तथा सामुदायिक जागरूकता पैदा करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र की जैव-विविधता को सुरक्षा मिलती है तथा जंगलों में विनाशकारी आग का जोखिम कम होता है। समय आ गया है कि जंगलों में आग की विभीषिका से निपटने के लिए एक समग्र रणनीति तैयार की जाए। उत्तराखंड सरकार को कैलीफोर्निया में अमेरिकी अनुभवों से भी समुचित सबक सीखने चाहिए जहां ऐसी आग अक्सर लगती है, लेकिन उस पर शीघ्र चेतावनी व्यवस्था के कारण बहुत अच्छी तरह व तेजी से नियंत्रण कर लिया जाता है। नैनीताल के जंगल में लगी आग हमारे प्राकृतिक परिस्थितिकी तंत्र की संवेदनशीलता के साथ ही अदम्य मानव भावना भी प्रकट करती है। अधिकारियों, सशस्त्र बलों तथा स्थानीय समुदायों के संयुक्त प्रयासों से आग को जल्दी ही बुझा दिया जाएगा। लेकिन यह संकट उत्तराखंड तथा अन्य क्षेत्रों में ज्यादा मजबूत व टिकाऊ व्यवस्था बनाने की दिशा में प्रेरक की भूमिका निभाने वाला भी होना चाहिए।

खामियाजा भुगतता पाकिस्तान

पाकिस्तानी राजदूत आसिफ दुर्रानी ने अफगानिस्तान की स्थिति से निपटने में पाक सरकार की गलतियां स्वीकार की हैं। इस प्रकार उन्होंने इस्लामाबाद की विदेश नीति का यथार्थ रेखांकित किया है।

भोपिंदर सिंह
(लेखक, सेवानिवृत्त सेनाधिकारी हैं)

पाकिस्तानी राजदूत राजदूत आसिफ दुर्रानी ने अफगानिस्तान की स्थिति से निपटने में पाक सरकार की गलतियां स्वीकार की हैं। इस प्रकार उन्होंने इस्लामाबाद की विदेश नीति का यथार्थ रेखांकित किया है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के विशेष प्रतिनिधि एवं उसके राजदूत आसिफ दुर्रानी ने अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सरकार की भयानक विफलता का कठोर यथार्थ स्वीकार किया है। 'पाकिस्तान इन द इमर्जिंग जिया-पालिटिकल लैंडस्केप', यानी उभरते भू-राजनीतिक परिदृश्य में पाकिस्तान की स्थिति पर आयोजित एक सम्मेलन में बोलते हुए राजनयिक ने स्वीकार किया कि अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा ड्यूरंड रेखा के दोनों ओर भड़के तनावों का खामियाजा भारत के साथ हुए सभी युद्धों के कुल मानवीय व वित्तीय खामियाजों से भी अधिक है। इस्लामाबाद वर्ष 2001 में कथित 'आतंक के खिलाफ युद्ध' में शामिल हुआ था। इसके सटीक व डरा देने वाले आंकड़ों के अनुसार, 80,000 से अधिक लोगों की जानें गई हैं।

इनमें लगभग 8,000 सुरक्षा बलों के जवान शामिल हैं। इसके साथ ही लगभग 150 बिलियन डालर का आर्थिक नुकसान भी हुआ है। इतना भारी नुकसान पाकिस्तान के लिए चिन्ता का विषय होना चाहिए। इससे परंपरागत 'नियंत्रण रेखा' या 'ड्यूरंड रेखा' के पार से होने वाला नुकसान स्पष्ट हो जाता है। इस्लामाबाद के लिए स्थिति इस तथ्य से और खराब होती है कि उसकी समस्यायें जल्दी समाप्त होती नहीं दिख रही हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान-टीटीपी द्वारा होने वाले घातक हमलों में 65 प्रतिशत तथा उससे जुड़े आत्मघाती हमलों में 500 प्रतिशत वृद्धि हुई है। ऐसे परिदृश्य में भारत को 'दुश्मन नंबर एक' मानते रहने की भावना एक प्रकार से कूपमंडूकता का उदाहरण है। इस दृष्टिकोण के कारण पाकिस्तान अपने चारों ओर स्वयं द्वारा किए जाने वाले 'कर्मों' के कठोर विनाशकारी परिणामों को स्वीकारने से भी इनकार करता है।

भारत के प्रति पाकिस्तान के संकुचित दृष्टिकोण का संबंध विभाजन के घावों से है। इसके साथ ही वह अपने नागरिकों की नजर में स्वयं को वैध ठहराने के लिए एक 'दुश्मन' की कल्पना में लगा रहता है। पाकिस्तान के विभिन्न संस्थान इसी काम में लगे रहते हैं जिनमें धर्मगुरु, सेना, राजनेता, आदि शामिल हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान विफल हो चुके 'द्विराष्ट्र सिद्धान्त' को भी वैध ठहराने में लगा रहता है क्योंकि इसी आधार पर वह अपने अस्तित्व को तार्किक बताता है। लेकिन 1971 में बांग्लादेश के जन्म ने उस देश की अनैतिकता को उजागर कर दिया है जिसका गठन धर्म के आधार पर हुआ था। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच वर्तमान टकराव सह-धर्मियों के बीच संबंधों की अव्यावहारिक स्थिति भी स्पष्ट करता है। इससे स्पष्ट होता है कि धर्म कभी भी राष्ट्रीयता का आधार नहीं बन सकता है तथा यह पड़ोसी समान धर्म वाले देश के साथ 'बिरादराना संबंधों' की भी कोई गारंटी नहीं है जिसका बार-बार दावा किया जाता रहा है। पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच लगातार बढ़ते टकराव से यह बात पूरी तरह सिद्ध होती है। कुल मिला कर ऐसे मामलों में 'उद्देश्य' का ही महत्व होता है। कुल मिला कर उद्देश्य ही आत्माभिव्यक्ति का माध्यम है जिसे सह-धार्मिकता के नाम पर अच्छी-अच्छी बातों से कुचला नहीं जा सकता है।

राजदूत आसिफ दुर्रानी ने अपने भाषण में स्वीकार किया है कि 'नाटो बलों के चले जाने के बाद उम्मीद की गई थी कि अफगानिस्तान में शांति से इस पूरे क्षेत्र में शांति पैदा होगी। लेकिन ऐसी उम्मीदें ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहीं।' इतिहास के बारे में जरा भी समझ रखने वाला कोई व्यक्ति आसानी से समझ लेगा कि अफगानिस्तान में विमर्श पर 'नियंत्रण' की इच्छा न केवल असंभव व अव्यावहारिक थी, बल्कि इसके विपरीत परिणाम अपरिहार्य थे। यह बात इस कारण भी सही है कि अफगानिस्तान कई बार 'ग्रेट गेम' का मैदान बना है। सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान में 'रणनीतिक प्रभुत्व' रखने की इच्छा अफगान तालिबान के गठन के समय से ही स्पष्ट थी। जहां अफगानों ने 1970 के दशकांत से सभी प्रकार की पाकिस्तानी सरकारों तथा उसकी ढांचागत संरचना की सहायता स्वीकार की, वहीं यह भी पूरी तरह स्पष्ट था कि गर्वीले अफगान आंख बंद कर इस्लामाबाद की बात मानने के लिए तैयार नहीं थे, भले ही यह पाकिस्तान द्वारा बनाए तालिबान के माध्यम से हो। यह बात अफगानों की सांस्कृतिक-सभ्यतामूलक पहचान के विपरीत थी। इसी विशिष्ट पहचान के चलते न केवल तालिबान सरकार ने इस्लामाबाद के सारे नियंत्रणों को तोड़ दिया, बल्कि इस्लामाबाद के 'सलाहकारों' तथा उनकी ओर से की जाने वाली अच्छी-अच्छी बातों को भी अस्वीकार कर दिया। इसके साथ ही उसने जानबूझ कर पाकिस्तान-विरोधी तहरीके तालिबान पाकिस्तान-टीटीपी जैसे वैचारिक संगठनों को पाला-पोसा जो धड़ल्ले से पाकिस्तान पर हमला करते हैं तथा उसके विनाशकारी नतीजे सामने आ रहे हैं।

स्थिति के गंभीर आंकलन से स्पष्ट है कि पाकिस्तान पर होने वाले हमले केवल अफगानिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों में व्याप्त असंतोष की परिघटना नहीं है, बल्कि इसका 'चिन्ताजनक आयाम ऐसे हमलों में अफगान नागरिकों की सहभागिता' है। मूलत: पहले ऐसे हमलों के पीछे अभिप्रेरित या प्रशिक्षित हत्यारे शामिल होते थे, पर अब पाकिस्तान पर अफगान नागरिक भी हमले कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तानियों द्वारा भारत को 'राक्षस' की तरह पेश करने की अवधारणा कट्टरपंथी अफगानों में पूरी तरह विफल हो गई है। इसका कारण यह है कि भारतीयों के प्रति उनकी भी स्पष्ट समझदारी है जो पाकिस्तान से पूर्णत: उलट है। कुल मिला कर हाल में इस्लामाबाद और दिल्ली से प्रकट होने वाली संप्रभु इच्छाओं में अंतर स्पष्ट दिख रहा है। अपनी स्वनिर्मित छवि, विचारधारा एवं अंतर्निहित कट्टरता जैसी कुछ सीमाओं से अलग तालिबान अधिकारियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा उस स्थिति से बिल्कुल अलग है जब अमेरिकी-नाटो बलों ने काबुल छोड़ा था और तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था।

आज पाकिस्तान सरकार स्वयं को अफगानिस्तान में अजीब स्थिति में पा रहा है जहां उसने भारी 'अवैध' निवेश किया था। विडंबना है कि पाकिस्तान स्वयं को अफगानिस्तान की इन विरोधाभासी स्थितियों से बाहर भी नहीं निकाल पा रहा है। पाकिस्तान इस बात के पूरे गंभीर प्रयास कर रहा है कि वह अपने उन कदमों के परिणामों से मुक्ति पा सके जो उसने वर्तमान अफगान सरकार, उसकी ढांचागत संरचना तथा क्षेत्र में उसके उद्देश्यों को बनाने के लिए उठाए थे। पाकिस्तानी राजदूत आसिफ दुर्रानी ने दु:ख प्रकट करते हुए कहा कि 'अफगानिस्तान पिछले चार दशकों से पाकिस्तान की क्षेत्रीय अवधारणा में स्थाई समस्या बन गया है।' इस प्रकार अब अफगान पाकिस्तान द्वारा इतने वर्षों में तालिबान और अफगान सरकार को दिए समर्थन को अपने दृष्टिकोण से देख रहे हैं। मजेदार बात है कि अफगानिस्तान में स्थिति के बारे में पाकिस्तान द्वारा की जाने वाली शिकायतों पर तालिबान सरकार व अफगान नागरिक जरा भी ध्यान नहीं देते हैं। वर्तमान समय में विश्व समुदाय और स्वयं पाकिस्तान भी यह अच्छी तरह समझ रहा है कि अफगानिस्तान के मामले में आखिरकार गलती कहां हुई। एक प्रकार से यह पाकिस्तान द्वारा 'शोर-शराबा' मचाने वाली स्थिति की तरह है, लेकिन उसकी बात ज्यादा लोग नहीं सुन रहे हैं और पाकिस्तान के कष्टों से किसी को कोई हमदर्दी नहीं है। गहरी नजर डालने से स्पष्ट होगा कि 1947 में गठित पाकिस्तानी व्यवस्था की सोच में ही सड़न व्याप्त थी, जब उसने सोचा था कि धर्म उसका ट्रंप कार्ड है। इस प्रकार इतिहास यह बात पूरी तरह स्पष्ट करता है कि धर्म कभी भी किसी देश की 'राष्ट्रीयता' का नैतिक या टिकाऊ आधार नहीं बन सकता है। बांग्लादेश और अफगानिस्तान, दोनों ने 'द्विराष्ट्र सिद्धान्त' को खारिज कर दिया है।

स्वयं की अस्मिता का संकट

> सबसे पहले मनुष्य को इस सत्य से अवगत कराया जाना चाहिए कि उसके अंदर दैवीय गुणों की एक निश्चित क्षमता या मानवीय मूल्यों का मूल है और ये गुण या मूल्य, उसके भीतर, अवचेतन के समुद्र में गहराई तक चले गए हैं।

ब्रह्म कुमार निकुंज
(लेखक, आध्यात्मिक चिंतक हैं)

न तो मनुष्य के अच्छे कर्म हमेशा के लिए अप्राप्त रहते हैं और न ही वह अपने बुरे कर्मों के लिए दण्ड से बचता है। आज, दुनिया का लगभग हर देश एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है जो सभी प्रकार के भय और असुरक्षाओं से मुक्त हो और सभी के लिए सुरक्षित हो। हालाँकि, इस पूरी कवायद में हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि बदलाव लाने की इंसान की कोशिशों में सफलता तभी मिलती है, जब उसे अपनी असली पहचान का पता चलता है। वर्तमान विश्व संकट, जिसे आम तौर पर मूल्यों का संकट कहा जाता है, वास्तव में अस्मिता का गहरा संकट है। मूल्यों का यह संकट स्वयं की वास्तविक पहचान के ज्ञान के लुप्त हो जाने के कारण भी उत्पन्न हुआ है। जबकि मनुष्य ने दुनिया भर में कई खोए हुए महाद्वीपों या भूमि खंडों की खोज की है, स्वयं के इस महाद्वीप को हम सभी द्वारा अभी तक खोजा या फिर से खोजा नहीं जा सका है। इस प्रकार सबसे पहले मनुष्य को इस सत्य से अवगत कराया जाना चाहिए कि उसके अंदर दैवीय गुणों की एक निश्चित क्षमता या मानवीय मूल्यों का मूल है और ये गुण या मूल्य, उसके भीतर, अवचेतन के समुद्र में गहराई तक चले गए हैं। और अचेतन मन को अब फिर से सतह पर, प्रकाश में लाना होगा और कार्यों के लिए कीबोर्ड के रूप में उपयोग करना होगा। मनुष्य को इस सत्य का भी बोध कराना होगा कि शव के दाह-संस्कार या दफ़नाने के साथ ही मनुष्य के जीवन काल में किये गये सभी अच्छे-बुरे कर्म, या कुछ समय में उसके द्वारा अर्जित की गयी योग्यताएँ और गुण, सब कुछ नहीं हैं। सब खो गया.

जब तक मनुष्य को यह एहसास नहीं होता कि, वास्तव में, वह एक शाश्वत प्राणी है, एक आत्मा है या एक प्रकाश-सत्ता है और अन्य प्राणी भी ऐसे ही हैं, तब तक उसके दृष्टिकोण और अन्य सभी के प्रति उसके दृष्टिकोण में पूर्ण परिवर्तन नहीं होता है। हालाँकि, जब उसे अपनी वास्तविक पहचान का एहसास होता है, तो वह एक नया मानसिक और आध्यात्मिक जन्म लेता है और फिर उसके स्वयं में और दूसरों के साथ उसके संबंधों में स्वचालित और स्वाभाविक रूप से सुधार होता है, यहाँ तक कि दिन के बाद रात भी होती है। इसलिए, हम जो भी रणनीति हमें किसी विशेष देश या लोगों के समूह के लिए उपयुक्त लगे, अपना सकते हैं, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि, देर-सबेर, हमें अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों को वास्तविक ज्ञान देना होगा। स्वयं की पहचान, क्योंकि इस ज्ञान के बिना, एक बेहतर दुनिया के हमारे लक्ष्य के करीब जाना संभव नहीं है।

आज हम सभी स्वयं को उस शरीर से पहचानते हैं जिसे हमने प्राप्त किया है क्योंकि हम आत्मा नामक अमर इकाई से अनजान हैं जो हमारे भीतर निवास करती है और हमारे शरीर के माध्यम से कार्य करती है। आत्मा के अस्तित्व के बारे में यह अज्ञानता इस प्रकार शरीर-चेतना या जीवन के प्रति सांसारिक दृष्टिकोण में परिणत होती है, जिसके परिणामस्वरूप जीवन भर हम इस तथ्य को समझे बिना अपने जीवन की स्थिति को सुधारने के लिए संघर्ष करते हैं कि शारीरिक और मानसिक क्यों दो व्यक्तियों की परिस्थितियाँ और वातावरण उनके जन्म के समय से ही काफी भिन्न होते हैं। हम प्राकृतिक आपदाओं, आतंकवाद, हिंसा और युद्धों के कारण बड़े पैमाने पर होने वाली मानवीय पीड़ाओं और असामयिक मौतों से चकित हो जाते हैं, जिसके कारण हमें हर समय अपनी मृत्यु का डर सताता रहता है।

इस पूरे मौज-मस्ती में, हम यह महसूस करने में असफल हो जाते हैं कि जब तक जीवन के इन बुनियादी पहलुओं को सही ढंग से नहीं समझा जाता है, तब तक शरीर के प्रति सचेत दृष्टिकोण बना रहेगा। किसी के भौतिक अस्तित्व को सबकुछ और सब कुछ का अंत मानने के परिणामस्वरूप मनुष्य जीवन में गलत मूल्यों को अपनाता है जिसके परिणामस्वरूप वह गलत कार्य करता है और परिणामस्वरूप उसे पीड़ा होती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी वह जीवन में दु:ख और कष्टों से बच नहीं पाता। इसलिए शांतिपूर्ण, संतुष्ट, सुखी और मुक्त जीवन जीने के लिए, अपने वास्तविक स्वरूप यानी आत्मा, उसकी कार्यप्रणाली और विश्व नाटक में उसकी भूमिका का उचित ज्ञान आवश्यक है।

आप की बात

राहुल के बयान

राहुल गाँधी ने कहा कि उड़ीसा में बीजेडी-बीजेपी की और तेलंगाना में बीआरएस-बीजेपी की शादी हो गई है तथा दिल्ली की सत्ता को 22-25 अरबपति चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आई तो सुविधाओं का खजाना खोल दिया जाएगा। लेकिन पहले तो कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट व अन्य विपक्षी नेता सड़कों पर चिल्ला-चिल्ला कर कहते थे कि कांग्रेस की सरकार को टाटा, बिड़ला, डालमिया पूंजीपति चला रहे हैं। राहुल को समझना चाहिए कि जनता को अपनी पार्टी की सच्चाई बतायें और वोट मांगे। राहुल गांधी करोड़ों लोगों को लखपति बनाने की बात करते हैं और उन्होंने गारंटियों का अंबार लगा दिया है। लेकिन वे यह नहीं बताते हैं कि इसके लिए पैसा कहां से आएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि वे स्वयं को सत्ता तक पहुंचाने के लिए मध्य वर्ग पर भारी टैक्स लगाने तथा विरासत कर के माध्यम से जनता की पैतृक संपत्ति हड़पने के चक्कर में हैं? वैसे राहुल वे सारे फार्मूले पेश कर रहे हैं जो अतीत में फेल हो चुके हैं तथा अधिकांश अर्थशास्त्रियों की नजर में अव्यावहारिक हैं। पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा कह चुके हैं कि ऐसी गारंटियां वही दे सकता है जिसे अपने सत्ता में वापस न आने का पूर्ण विश्वास हो। राहुल अपनी विश्वसनीयता खो रहे हैं।

– **शकुंतला महेश नेनावा,** इंदौर

वासुकी नाग के अवशेष

गुजरात में मिले वासुकी नाग के अवशेषों ने भारतीय वैज्ञानिकों और संस्कृति प्रेमियों में नया उत्साह भर दिया है। अवशेष 15 मीटर लंबे और लगभग 1 टन वजनी नाग के थे, जिसे वासुकी इंडिकस के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने की थी। वासुकी नाग की यह खोज भारतीय संस्कृति और इतिहास के साथ-साथ विज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण है। इस खोज ने हमें हमारे पुराणों में वर्णित वासुकी नाग की याद दिलाई जो भगवान शिव के गले में विराजमान है। वैज्ञानिकों ने इस प्रजाति का नाम भी इसी पौराणिक सांप के नाम पर रखा है जो हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का सम्मान है। वासुकी नाग की खोज से हमें यह संकेत मिलता है कि भारत की भूमि में और भी अद्वितीय और रहस्यमय जीवाश्म छिपे हो सकते हैं। वासुकी नाग के अवशेषों की खोज हमारे वैज्ञानिकों के लिए एक प्रेरणास्रोत है। उनको ऐसी अन्य खोजों पर भी ध्यान देना चाहिए जो भारतीय प्राचीन मान्यताओं, पौराणिक अवधारणाओं तथा प्राचीन विज्ञान को आधुनिक विज्ञान से जोड़ती हों। इससे भारत सचमुच विरासत के साथ विकास से भी जुड़ सकता है। यह भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत होगा।

– **अवनीश कुमार गुप्ता,** आजमगढ़

युद्धों का माहौल

रूस-यूक्रेन युद्ध इतना लंबा खींचेगा इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यूक्रेन इतना शक्तिशाली था भी नहीं कि वह रुस से इतने लंबे समय तक युद्ध कर सके। मगर अमेरिका और नाटो देशों द्वारा भारी मात्रा में हथियार व धन मिलने से यूक्रेन रूस से लोहा ले रहा है। भले ही युद्ध में उसे अमेरिका का पूरा साथ मिल रहा है, मगर नागरिक और सैनिक बड़ी संख्या में यूक्रेन के मर रहे हैं। यूक्रेन तहस-नहस और बर्बाद हो चुका है। एक समय आर्थिक रूप से मजबूत यूक्रेनी जनता के बहुत से लोग शरणार्थी बनकर दाने-दाने के मोहताज हो गए हैं। अब अमेरिका भी अपने देश के भीतर चल रहे युद्ध-विरोधी प्रदर्शनों के कारण फूंक-फूंक कर कदम रख रहा है। इज़राइल-हमास संघर्ष भी दुनिया को संकट में धकेल रहा है। हूती विद्रोही लगातार समुद्र में व्यापार और नौवहन को खतरे में डाल रहे हैं। इन परिस्थितियों से निपटने में विफलता के कारण इस वर्ष होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। ऐसे में अमेरिका को राजनयिक प्रयासों तथा दुनिया में सभी देशों से बात कर युद्धों का माहौल समाप्त करवाने के प्रयास करने चाहिए। युद्धों का माहौल सारी मानवता के लिए खतरनाक है।

–**विभूति बुपक्या,** खाचरोद

मतदान का स्तर

संभवत: पहले चरण के मतदान में आई गिरावट को प्रशासन या राजनीतिक दलों ने गंभीरता से नहीं लिया है। यही वजह है कि दूसरे चरण में फिर पिछले चुनाव के मुकाबले 9.39 प्रतिशत की कमी आई है। अभी लोकसभा चुनाव के दो ही चरण संपन्न हुए हैं और पांच चरण बाकी है। हालांकि, भीषण गर्मी के चलते आम आदमी बेहाल है और वह वैवाहिक आयोजनों तथा फसल कटाई के काम में भी उलझा हुआ है, फिर भी हम राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को कैसे भूल सकते हैं? अगले पांच चरण के लिए हर नागरिक को फिक्रमंद होकर मतदान प्रतिशत बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए। जहां तक संभव हो सके मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि लंबी कतारें न लगें और लोग जल्द वोट डाल सके। चुनाव के अगले चरणों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग के साथ ही सभी नागरिकों व राजनीतिक दलों की भी है। सभी राजनीतिक दलों को संयुक्त रूप से मतदान की अपील करनी चाहिए। इसमें स्वयंसेवी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं व धर्मगुरुओं की विशेष भूमिका हो सकती है।

– **अमृतलाल मारू,** इन्दौर

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से
responsemail.hindipioneer@gmail.com
पर भी भेज सकते हैं।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 63

क्षमता निर्माण

इस समाचार पत्र में सोमवार को प्रकाशित खबर के मुताबिक रेल मंत्रालय 200 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल निजी कंपनियों और फ्रेट ऑपरेटरों को देने पर विचार कर रहा है। इस कदम का स्वागत किया जाना चाहिए क्योंकि इससे न केवल रेलवे की जमीन तथा अन्य परिसंपत्तियों का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित होगा बल्कि लॉजिस्टिक क्षेत्र की क्षमता में भी सुधार होगा। सरकार के अनुमानों के मुताबिक 200 नए टर्मिनल बनाने में करीब 12,000 से 14,000 करोड़ रुपये का निवेश करना होगा। यह कदम सितंबर 2022 में घोषित नीति को और आगे ले जाएगा। उस समय केंद्र सरकार ने रेलवे की जमीन को कॉर्गो प्रबंधन तथा सार्वजनिक उपयोग जैसी गतिविधियों के लिए पट्टे पर देने के लिए एक नीति को मंजूरी प्रदान की थी। इस नीति में अगले पांच वर्षों में तीन गति शक्ति टर्मिनल बनाने की योजना शामिल थी।

यह नीति व्यापक तौर पर रेलवे की जमीन को दीर्घकालिक रूप से पट्टे पर देने से संबंधित है ताकि उस जमीन का इस्तेमाल 35 सालों तक कार्गो संबंधी सुविधाओं के लिए किया जाए। इसके लिए जमीन के वाणिज्यिक मूल्य का सालाना 1.5 फीसदी शुल्क तय किया गया है। यह आवंटन प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से किया जाता है और कार्गो टर्मिनल के विकास से अनुमानतः 1.2 लाख लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। रेलवे की योजना है कि 100 टर्मिनल के पूरा होने के बाद 200 कार्गो टर्मिनल की बोली प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरी कर ली जाए। फिलहाल ऐस 77 कार्गो टर्मिनल शुरू हो चुके हैं और इस पर करीब 5,400 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। ऐसी सुविधाओं का संचालन करने वाले कुछ बड़े नामों में कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अदाणी ग्रुप, जेएसडब्ल्यू ग्रुप, इंडियन ऑयल और नायरा एनर्जी शामिल हैं।

समय के साथ 300 कार्गो टर्मिनल बनाने की नीति से रेलवे तथा समूची अर्थव्यवस्था को कई फायदे होंगे। रेलवे को इस क्षेत्र में अतिरिक्त व्यय नहीं करना होगा। सफल बोली लगाने वाले उसके निर्माण की लागत वहन करेंगे और कारोबारी जोखिम भी उन्हीं का होगा जबकि स्वामित्व रेलवे के पास रहेगा। बेहतर लॉजिस्टिक से अतिरिक्त कार्गो ट्रैफिक मिलेगा और रेलवे का राजस्व बढ़ेगा। अनुमान के मुताबिक हर नया कार्गो टर्मिनल सालाना 10 लाख टन की क्षमता वृद्धि संभावना से लैस होगा। यानी करीब 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जुटाई जा सकेगी।

अक्सर यह दलील दी जाती है कि भारतीय रेल के पास बहुत अधिक जमीन है और उसका सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। कार्गो सुविधाओं का निर्माण करने से रेल परिसंपत्तियों का किफायती इस्तेमाल सुनिश्चित होगा। इन स्थानों पर बेहतर कार्गो सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं जिनमें कई मूल्यवर्द्धित सेवाएं शामिल हैं। इससे देश में आंतरिक व्यापार को भी गति मिलनी चाहिए। इससे क्षमता सुधरेगी और कारोबारी सुगमता में भी इजाफा होगा। लॉजिस्टिक की ऊंची लागत अक्सर कारोबारी सुगमता की राह में बड़ी बाधा होती है। हालांकि बीते कुछ सालों में सड़क अधोसंरचना में भी काफी सुधार हुआ है लेकिन रेलवे के माध्यम से माल ढुलाई अधिक किफायती है क्योंकि इसका प्रबंधन अच्छे से होता है और सुदूर संपर्क की भी कोई समस्या नहीं है। 300 कार्गो टर्मिनल का विकास और गति शक्ति प्लेटफॉर्म का डिजाइन अधोसंरचना विकास दर्शाता है और इससे लंबे समय से चली आ रही कुछ बाधाएं दूर हो रही हैं। भारतीय रेल के कार्गो कारोबार का काफी हिस्सा सड़क क्षेत्रों के पास चला गया है। ऐसा मोटे तौर पर उसके गैर किफायती होने तथा सड़क ढांचे में महत्त्वपूर्ण सुधार की वजह से हुआ है। बहरहाल, कार्गो टर्मिनल का विकास तथा महत्त्वपूर्ण सरकारी पूंजी व्यय के साथ रेलवे की समग्र क्षमता में सुधार से उसे माल ढुलाई में खोई हुई हिस्सेदारी वापस पाने में मदद मिलनी चाहिए। इससे देश के कार्बन उत्सर्जन में भी कमी लाने में मदद मिलेगी।

वृद्धि में बाधक श्रम नियमों पर पुनर्विचार जरूरी

देश की आईटी राजधानी जल संकट जैसी वजहों से अखबारों की सुर्खियों में रही है। आईटी/आईटीईएस से जुड़े क्षेत्र के कर्मचारियों के बीच भी असंतोष पनपने के संकेत मिल रहे हैं। बता रहे हैं के पी कृष्णन

कर्नाटक राज्य आईटी /आईटीईएस कर्मचारी संघ (केआईटीयू) नाम के एक नए श्रमिक संघ ने मांग की है कि राज्य सरकार आईटी/आईटीईएस प्रतिष्ठानों को 1946 के औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम से दी गई लंबे समय से चली आ रही छूट को खत्म कर दे। कर्नाटक में आईटी और इससे जुड़ी सेवाओं के क्षेत्र में लगभग 20 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं और ऐसा लगता है कि केआईटीयू के लगभग 10,000 सदस्य हैं।

इस श्रमिक संगठन ने कहा कि छूट के चलते नियोक्ताओं ने श्रम नियमों का उल्लंघन किया जैसे कि नियोक्ता कई घंटे की लंबी कार्यावधि लागू करते हैं लेकिन वे सुरक्षा से जुड़ी शिकायतें (यौन उत्पीड़न सहित) दर्ज करने के लिए कोई बेहतर तंत्र देने में विफल रहते हैं और अनुचित तरीके से श्रमिकों की कार्यसेवा समाप्त कर देते हैं।

विचाराधीन कानून विशेषतौर पर श्रमिकों को कोई सुरक्षा नहीं देता है और इसका उद्देश्य केवल पारदर्शिता के स्तर को बढ़ाना और अन्य कानूनों में श्रमिकों को दिए गए गारंटीयुक्त अधिकार से जुड़ी समझ को सुधारना है। कर्नाटक में 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को सरकार द्वारा प्रमाणित 'स्थायी आदेशों' में श्रमिकों को सेवाओं की शर्तों को संहिताबद्ध करने के साथ ही इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। यह वांछनीय भी है।

लेकिन यह कानून, कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को यह मांग करने में भी सक्षम बनाता है कि नियोक्ता कानूनी आवश्यकताओं से ऊपर उठें और सेवा की इन शर्तों को छोड़ दें। कर्मचारियों से जुड़े नियमों और शर्तों में एकरूपता से जुड़े स्थायी आदेशों को अपनाने से पहले प्रतिष्ठानों को श्रमिक प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करने के लिए मजबूर किया जाता है। असहमति के मामले में, नियोक्ता को श्रमिक प्रतिनिधियों और सरकार के साथ त्रिपक्षीय चर्चा करनी चाहिए। इस तरह की स्थिति में नियोक्ता-कर्मचारी का संबंध फिर दो और पक्षों श्रमिक संगठनों और सरकार के साथ उलझ जाता है।

प्रमाणित स्थायी आदेशों की सामग्री को श्रमिक प्रतिनिधियों की सहमति के बिना छह महीने तक नहीं बदला जा सकता है। नियोक्ताओं को रोजगार की उन शर्तों को अपनाने के लिए कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के भारी दबाव का सामना करना पड़ता है जो किसी भी कानून के तहत अनिवार्य नहीं हैं।

उदाहरण के तौर पर केआईटीयू ने हाल ही में कार्यावधि के बाद किसी आधिकारिक संदेश को नजरअंदाज करने के अधिकार की वकालत करने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया है। इसके तहत 'काम के घंटे के बाद' सहकर्मियों और वरिष्ठों की तरफ से भेजे गए सभी आधिकारिक संदेशों को नजरअंदाज करने का अधिकार होगा और इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

हम उन श्रमिक प्रतिनिधियों के उद्देश्यों की सराहना कर सकते हैं जो अधिक अधिकार चाहते हैं लेकिन इसके नतीजे अर्थव्यवस्था पर देखे जा सकते हैं। यह कोई संयोग की बात नहीं है कि अधिकांश क्षेत्रों में भारतीय निर्यात पर असर देखा गया है।

भारत से वस्तु निर्यात वर्ष 2012-2022 की अवधि के लिए प्रति वर्ष 1.2 प्रतिशत की चक्रवृद्धि दर से बढ़ा (यानी यह 56 वर्षों में दोगुना हो गया)। इसी अवधि में, सेवाओं का निर्यात 5.7 प्रतिशत की चक्रवृद्धि दर से बढ़ा (यानी यह प्रत्येक 12 वर्षों में दोगुना हो गया)। क्या पारंपरिक भारतीय श्रम कानून वस्तुओं के निर्यात में बाधा बना जबकि दूसरी ओर सेवा निर्यात को बढ़ने का मौका दिया गया?

भारतीय परिधान निर्माताओं को अगर भारतीय सॉफ्टवेयर निर्माताओं के समान विशेषाधिकार दिया जाए तो उनकी उपलब्धियां क्या होंगी? उदाहरण के तौर पर, काम की अवधि के बाद संपर्क में न रहने (डिस्कनेक्ट) के अधिकार पर विचार करें। भारत का आईटी/आईटीईएस क्षेत्र वैश्विक स्तर पर सभी क्षेत्रों के ग्राहकों को सेवाएं देता है जिनकी समयावधि में काफी अंतर है। ऐसे में भारतीय आईटी/आईटीईएस कंपनियों के लिए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखना मुश्किल होगा जब कर्मचारी अपनी काम की समय-सीमा पूरी हो जाने के बाद विदेश में अपने टीम के लोगों या ग्राहकों की कॉल लेने से इनकार करते हैं।

मौजूदा लचीले तंत्र में प्रबंधक और कामगार बीच का रास्ता खोजते हैं जो उपयुक्त हो और जहां कुछ लोग देश में रात के काम की बाधाओं को दूर करने के लिए तैयार होते हैं। इस तरह की व्यावहारिक समस्या का समाधान 'त्रिपक्षीय प्रणाली' से निश्चित रूप से बाधित होगा जिसमें उदाहरण के तौर पर श्रमिक संगठन और सरकार के साथ-साथ कंपनी और कर्मचारी भी जुड़े होंगे।

क्या श्रमिक संगठनों और सरकार को असहाय कामगारों को सुरक्षा देने की जरूरत है? अब कई क्षेत्रों में भारत में शिक्षित कामगारों का एक ऐसा वर्ग है जो अपने निजी हितों का खयाल रखने में सक्षम है। जब कोई कंपनी किसी कर्मचारी के साथ सही बरताव नहीं करती है तब ऐसे कर्मचारी नौकरी छोड़ने का चयन कर सकते हैं और करते हैं।

शिक्षित कर्मचारियों के पास श्रम बाजार का विकल्प है। वेतन में कमी और बढ़ोतरी होती है जो आपूर्ति और मांग को दर्शाता है। कोई कामगार जो दफ्तर की कार्यावधि के बाद संपर्क में नहीं रहना चाहता है तो उसे ऐसी कंपनी भी मिल सकती है जो कम वेतन पर इस तरह की सहूलियत की पेशकश कर सकती है। इन निजी मोल-तोल वाली बातचीत में राज्य के दबाव और किसी श्रमिक संगठन द्वारा मध्यस्थता किए जाने की जरूरत नहीं है।

जब आईटी कंपनियों के लिए स्थायी आदेशों को समाप्त कर दिया गया था तब कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण (पीओएसएच) कानून और औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों को विशेष शर्तों के रूप में दोहराया गया। आईटी /आईटीईएस कंपनियों को यौन उत्पीड़न के मामलों और अन्य शिकायतों से निपटने के लिए समितियों का गठन करने और श्रम विभाग को बर्खास्तगी के मामलों की रिपोर्ट देने की आवश्यकता थी। नया श्रमिक संगठन केआईटीयू यह आरोप लगाता है कि कई आईटी /आईटीईएस कंपनियां इन शर्तों का पालन नहीं करती हैं।

इन शर्तों के साथ राज्य सरकार द्वारा अनुपालन की निगरानी में हुए सुधार का अपना ही फायदा है। खासतौर पर ज्यादा सार्वजनिक खुलासा होने से कामगारों को किसी कंपनी के लिए काम करने या न करने का निर्णय लेने में मदद मिल सकती है।

इन सवालों में कर्नाटक में आईटी/आईटीईएस क्षेत्र दांव पर लगा है जो राज्य की अर्थव्यवस्था का केंद्र है। लेकिन भारत से सेवा निर्यात के लिए नीतिगत परिस्थितियां भारत के भविष्य के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। वर्ष 2022-23 में सेवा निर्यात 325 अरब डॉलर था और यह हर दशक में दोगुना हो सकता है। अगर राज्य सही फैसला लेता है तब आने वाले दशक में भारतीयों के पास निर्यात से 325 अरब डॉलर का राजस्व मिल सकता है। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की तुलना में देखा जाए तो ये आंकड़े काफी बड़े हैं। अगर इन क्षेत्रों पर सही तरीके से ध्यान नहीं दिया गया तब भारत का आर्थिक भविष्य जोखिम में होगा।

इसके अलावा हमें आखिरकार आईटी और आईटीईएस से इतर भी सोचना चाहिए। आईटी और आईटीईस में ऐसा विशेष क्या है जिसके लिए श्रम कानूनों से जुड़ी समस्या को हल किया गया लेकिन दूसरे क्षेत्रों के लिए ऐसे कदम नहीं उठाए गए। क्या भारत में आईटी और आईटीईएस से इतर भी अन्य क्षेत्र हो सकते हैं या कोई अन्य कारोबारी सेवाएं हो सकती हैं जहां आईटी और आईटीईएस क्षेत्र जैसी ही उपलब्धियों को दोहराया जा सकता है? इस क्षेत्र को दी गई छूट एक संकेतक के तौर पर ली जानी चाहिए ताकि विनिर्माण सहित अन्य सेवाओं के लिए भी समान तरह का लचीलापन बरता जाए क्योंकि अपरिकल्पित श्रम नियमन, कंपनियों की वृद्धि और रोजगार के मौके के लिए बाधा बताए जाते हैं।

श्रम कानूनों की संरचना को तय करते वक्त कर्नाटक जैसी सरकारों को उद्योग के बजाय कर्मचारियों की एजेंसी पर ध्यान देने की जरूरत है। श्रम कानूनों की संरचना में किसी ऐसी कंपनी के लिए समान रूप से छूट दी जा सकती है जहां 85 फीसदी से अधिक कर्मचारी कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई तुरंत करके आए हैं।

(लेखक पूर्व लोक सेवक और आइजैक सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी में मानद वरिष्ठ फेलो हैं)

म्युचुअल फंड की जोखिम जांच कितनी उपयोगी?

इस वर्ष के शुरू में बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने म्युचुअल फंडों को उनकी योजनाओं में रकम का अंधाधुंध प्रवाह नियंत्रित करने एवं पोर्टफोलियो में बदलाव करने के निर्देश दिए थे। नियामक ने यह निर्देश इसलिए दिया था कि बेरोक-टोक निवेश आने से बाजार में अनिश्चितता बढ़ जाती है। एक साल तक स्मॉलकैप फंडों में भारी भरकम निवेश से बाजार नियामक चिंतित हो गया था और इसी वजह से फंड कंपनियों को ये निर्देश जारी किए गए।

सेबी ने म्युचुअल फंडों को स्मॉल एवं मिडकैप फंडों के लिए जोखिम जांच (स्ट्रेस टेस्ट) शुरू करने और इसका नतीजा प्रकाशित करने का भी निर्देश दिया। जोखिम जांच में तरलता (शेयरों का लेनदेन), अनिश्चितता, मूल्यांकन और पोर्टफोलियो टर्नओवर (पोर्टफोलियो में शेयर खरीदने या बेचने की रफ्तार) आदि आते हैं। सेबी ने फंड कंपनियों को दिशानिर्देश, सिद्धांत एवं विधियां सरल भाषा में बताने के लिए कहा ताकि निवेशकों को जोखिमों को ठीक ढंग से समझने में कोई परेशानी नहीं आए। संक्षेप में कहें तो इस जोखिम जांच का मकसद यह पता लगाना था कि स्मॉलकैप और मिडकैप पोर्टफोलियो को 25 प्रतिशत और 50 प्रतिशत हिस्सा बेचने में कितने दिन लग सकते हैं। रकम का प्रवाह नियंत्रित करना प्रत्यक्ष रूप से बाजार में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करना है (रकम आने से शेयरों में तेजी आती है और रकम तब आती है जब बाजार में धारणा एवं आय मजबूत रहती है) मगर जोखिम जांच एक अलग मसला है।

सेबी ने जोखिम जांच कराने के जो निर्देश दिए हैं उसके साथ तीन समस्याएं हैं। सबसे पहले जोखिम जांच तर्कसंगत नहीं लगती है। यह मान लिया गया है कि चढ़ते बाजार में होने वाले लेनदेन की दर गिरते बाजार में भी कम नहीं होगी। मगर बाजार में लेनदेन नाटकीय ढंग से बढ़ या घट सकते हैं। ऊपर चढ़ते बाजार में कई खरीदार और बिकवाल होते हैं। मगर जोखिम बढ़ने की स्थिति में खरीदार नहीं मिलते हैं और केवल बिकवाल ही चारों तरफ नजर आते हैं। कारोबार बिल्कुल नदारद रहता है। पोर्टफोलियो का 50 प्रतिशत या 25 प्रतिशत हिस्सा बेचने में कितने दिन लगेंगे यह बात बाजार के हालात पर निर्भर करेगी। ऐसे में अगर किसी धुरंधर पोर्टफोलियो प्रबंधक ने जोखिम जांच को 'फिजूल' कहा है तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जोखिम जांच में उन विकट परिस्थितियों पर विचार नहीं किया गया है जब बाजार में अफरातफरी, असमंजस, एक दूसरे की देखादेखी और बिना सोच-विचार के निर्णय लेने का दौर शुरू हो जाता है। बड़ा से बड़ा माहिर कारोबारी भी इन परिस्थितियों में उलझ कर रह जाता है।

अतार्किक विकल्प

देवाशिष बसु

दूसरी अहम बात यह है कि कोई निवेशक पोर्टफोलियो का एक हिस्सा बेचने में लगने वाले समय, स्टैंडर्ड डिविएशन, बीटा, पोर्टफोलियो टर्नओवर और प्राइस-टू-अर्निंग अनुपात जैसे मानकों को कैसे समझ पाएगा? वह यह कैसे तय करेगा कि प्रतिकूल मानकों वाले फंड से निकलकर एक बेहतर फंड में कैसे निवेश ले जाएं? उदाहरण के लिए किसी फंड में कम मूल्यांकन वाले शेयर हो सकते हैं (जो तेजी से गिरते बाजार मे कम फिसलते हैं) मगर इन्हें बेचने में लंबा समय लगता है। ऐसे में कोई निवेशक पहले फंड की खूबियों की तुलना दूसरे फंड की खामियों से कैसे करेगा? उस स्थिति में निवेशकों को अन्य मानकों जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन, पोर्टफोलियो बीटा और टर्नओवर रेश्यो पर विचार करना होगा। क्या इन सभी मानकों को महत्त्व देने और सभी फंडों को बराबर तरजीह देने और कुल स्कोर की गणना करने के बाद रैंकिंग तैयार करने की जरूरत नहीं है? अगर यह सब करना बहुत पेचीदा लगता है तो फिर इन मानकों का किस तरह बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या मैं वाकई जोखिम जांच के नतीजों के आधार पर फंडों की रैंकिंग कर सकता हूं? क्या इन मानकों पर अधिक स्कोर करने वाले फंड जोखिम समायोजित अधिक प्रतिफल देंगे? मैं यह कैसे जान पाऊंगा? क्या किसी ने यह परखने की कोशिश की है कि ये जोखिम जांच निवेश से संबंधित निर्णय लेने में कितने मददगार हैं?

अगर हम केवल एक महत्त्वपूर्ण कारक- पोर्टफोलियो का एक हिस्सा बेचने में लगने वाला समय- पर ध्यान केंद्रित करें तो उस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए जब मैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) में दीर्घ अवधि के लिए निवेश कर रहा हूं? स्मॉलकैप शेयरों में 82 प्रतिशत निवेश रखने वाले एसबीआई म्युचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो का 50 प्रतिशत हिस्सा बेचने में 58 दिन का समय लेगा मगर स्मॉलकैप में 83 प्रतिशत तक निवेश रखने वाला यूटीआई स्मॉलकैप फंड को केवल पांच दिनों का समय लेगा। दोनों में अंतर (हिस्सेदारी बेचने में लगने वाले समय में) इतना अधिक है कि यह तर्कसंगत नहीं लगता है (स्रोतः एसोसिएशन ऑफ म्युचुअल फंड्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट)।

तीसरी बात यह है कि सेबी उन शेयरों को स्मॉलकैप मानता है जिनका बाजार मूल्य 5,000 करोड़ रुपये से कम होता है। कई क्षेत्र और कई शेयरों ने बाजार की मौजूदा तेजी में डुबकी लगाई है। सरसरी निगाह डालने से पता चलता है कि 3,898 ऐसी कंपनियां हैं जिनका बाजार मूल्य 5,000 करोड़ रुपये से कम है और केवल 688 कंपनियां हैं जिनका मूल्य इससे अधिक है। इसका मतलब तो यह हुआ कि बाजार में 85 प्रतिशत शेयर स्मॉलकैप के रूप में परिभाषित किए गए हैं। यह सभी शेयरों को एक ही तराजू में तौलने के समान है जिसके खतरनाक परिणाम सामने आ सकते हैं। मेरा मानना है कि शेयरों को मौजूदा तीन श्रेणियों में विभाजित (लार्ज, मिड और स्मॉल) करना पर्याप्त नहीं है। हमें शेयरों को कम से कम पांच श्रेणियों में विभाजित करना चाहिए।

चौथी बात यह है कि जोखिम जांच उन कारकों पर बहुत अधिक जोर देते हैं जो फंड प्रबंधक के लिए विशेष मायने नहीं रखते हैं। शेयरों के चयन की कई विधियां होती हैं मगर सबसे लोकप्रिय विधि वह होती है जिसमें तार्किक मूल्यांकन पर दीर्घ अवधि की संभावनाओं वाले शेयर चुने जाते हैं। ऐसे शेयर अक्सर स्मॉल एवं मिडकैप श्रेणियों में पाए जाते हैं। इन शेयरों का चयन आसान नहीं है, खासकर बाजार में तेजी के दौरान ऐसा करना मुश्किल है। क्या अगर ऐसे शेयरों के लेनदेन कम होंगे तो फंड प्रबंधक इनकी अनदेखी कर देगा? बिल्कुल नहीं। मगर अब जोखिम जांच के तहत ऐसे शेयर का चयन तरलता के मानकों को नुकसान पहुंचाएगा। इन सभी बातों पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि जोखिम जांच का पूरा ताना-बाना कमजोर बुनियाद पर खड़ा है। किसी योजना में निवेश से संबंधित वैधानिक चेतावनी की तरह जोखिम जांच भी औपचारिकता बन कर रह जाएगी। इस चेतावनी का सैद्धांतिक महत्त्व है तो है मगर बहुत व्यावहारिक नहीं है।

(लेखक डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट मनीलाइफ डॉट इन के संपादक हैं और मनीलाइफ फाउंडेशन के न्यासी हैं)

आपका पक्ष

बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए आचार संहिता जरूरी

हाल में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के उत्पाद के बारे में सामने आया कि विकसित देशों के मुकाबले भारत में उसके उत्पाद में चीनी की मात्रा कहीं अधिक है। यह तथ्य रेखांकित करता है कि कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने उत्पादों या सेवाओं के लिए विकसित और विकासशील देशों के लिए अलग-अलग मानदंड बना रखे हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भारत की ओर बढ़ते रुझान के अनेक कारण हैं। भारत एक विस्तृत उपभोक्ता बाजार है। यह विश्व की सबसे तेज गति से विकासमान अर्थव्यवस्था है। साथ ही एफडीआई के प्रति सरकारी नीति की भी इसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। पिछले कुछ दशकों में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी प्रतिबंधित नीति रही है। परिणामस्वरूप कम संख्या और विशेष क्षेत्रों में ही विदेशी निवेश सीमित था। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने के सरकार के निरंतर प्रयास के तहत 'मेक इन इंडिया' अभियान

कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने उत्पादों या सेवाओं के लिए विकसित और विकासशील देशों के लिए अलग-अलग मानदंड बना रखे हैं

प्रारंभ किया गया जिससे कि विदेशी कंपनियां भारत में उत्पादन करें। विदेशी कंपनियां भारत में लाभार्जन के उद्धेश्य से ही आती हैं। भारत में भिन्न और नवीन उत्पादों का विस्तृत बाजार है। प्रतिस्पर्धी श्रम बाजार, विपणन और समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व अन्य प्रमुख कारण हैं, जिन्होंने विदेशी कंपनियों को भारत में आकर्षित किया है। भारत जैसे अन्य विकासशील देशों के सामने समस्या यह है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हानिकारक प्रभावों को किस प्रकार नियंत्रित और कम किया जाए और उनसे अधिकतम लाभ के लिए उपयुक्त नियम बनाए जाएं। अल्प विकसित और विकासशील देशों को इन कंपनियों की विशिष्ट तथा बेहतर तकनीकों तथा कार्यविधियों के बारे में स्पष्ट आचार संहिता बनानी चाहिए। उनके कार्यों के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करें ताकि इनके पक्षपातपूर्ण व दोहरे रवैये पर अंकुश लगाया जा सके।

सुधीर कुमार सोमानी, देवास

तनाव लंबा खिंचा तो असर ज्यादा

ईरान और इजरायल के बीच तनाव अगर लंबा रहा तो निश्चित ही भारत को आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ेगी। दोनों के बीच तनातनी के बाद ही तेल के दाम 90 अमेरिकी डॉलर तक जा पहुंचे हैं। भारत में भी प्रतिदिन लाखों गैलन कच्चा तेल ईरान, इराक, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर आदि देशों से आयात होता है। युद्ध के दौरान ईरान होमुर्ज जलडमरूमध्य मार्ग रोक देगा जिससे तेल का गंभीर संकट होगा। तेल की कीमतें बढ़ने से माल भाड़ा बढ़ेगा जिससे महंगाई बढ़ने लगेगी।

संजय डागा, इंदौर

खाड़ी के व्यापार चक्र पर असर

ईरान और इजरायल का तनाव भारत के साथ ही पश्चिम एशिया के देशों के कारोबार को प्रभावित करेगा। एशिया की 70 प्रतिशत से अधिक आवश्यकता का तेल ईरान से जाता है। इजरायल से भी भारत सहित मित्र देशों के व्यापारिक संबंध बने हुए हैं। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव और युद्ध की स्थिति में खाड़ी का व्यापार चक्र प्रभावित होगा। भारतीय कारोबार को अप्रत्याशित हानि संभावित है।

डॉ. हेमलता कर्नावट, इंदौर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

अफ्रीकी देश केन्या के ग्रेट रिफ्ट घाटी क्षेत्र के माई माहिउ इलाके में सोमवार सुबह एक बांध के टूटने से लगभग 40 लोगों की मौत हो गई। केन्या में बीते कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। बाढ़ के कारण अब तक करीब 100 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ का पानी कम होने के बाद गाद हटाने में जुटे स्थानीय लोग।

प्रवाह

महोत्सव विश्वास का 75
निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

शिक्षा स्वर्ग का द्वार खोलती है और खुद को जानने का अवसर देती है। -सावित्री बाई फुले

भारतीय नौसेना ने बेशक हूती विद्रोहियों के ताजा हमले को निष्फल कर दिया है, लेकिन इस्राइल-हमास जंग की शुरुआत से ही जिस तरह से ईरान समर्थित हूती विद्रोही लगातार हमले कर रहे हैं, उसने वैश्विक व्यवस्था के समक्ष एक नया संकट पैदा कर दिया है, जिसका शीघ्र समाधान तलाशना होगा।

हूती संकट

इस्राइल-हमास संघर्ष के बीच लाल सागर के रास्ते रूस से तेल ला रहे व्यापारिक जहाज एमवी अंड्रोमेडा स्टार पर हुए हूती विद्रोहियों के मिसाइल हमले पर भारतीय नौसेना के विध्वंसक पोत आईएनएस कोच्चि ने जिस मुस्तैदी से त्वरित जवाबी कार्रवाई करते हुए 22 भारतीयों समेत 30 क्रू सदस्यों की जानें बचाईं, वह उसके चिर-परिचित पराक्रम का एक और प्रमाण है। पिछले कुछ महीनों में हमारी नौसेना ने पश्चिमी हिंद महासागर में व्यापारिक जहाजों पर हुए कई हमलों को निष्फल किया है। दरअसल, इस्राइल-हमास जंग शुरू होने के बाद से ही ईरान समर्थित हूती विद्रोही लाल सागर और उसके आसपास व्यापारिक जहाजों को निशाना बना रहे हैं, जिसके चलते अमेरिका व इंग्लैंड के गठबंधन वाली सेना उन पर कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका और उसके सहयोगी एक ऐसे समूह के खिलाफ जीत सकते हैं, जिनसे लगभग एक दशक तक लड़ने के बावजूद सऊदी अरब नाकाम रहा। वास्तव में, हूती विद्रोहियों को असल ताकत 2011 में अरब क्रांति के बाद मिली, जब यमन में शिया-सुन्नी विवाद गृहयुद्ध में बदल गया। अरब जगत में दबदबा कायम करने की होड़ में संयुक्त अरब अमीरात और ईरान भी गृहयुद्ध में कूद गए। हूती विद्रोहियों को शिया बहुल ईरान का समर्थन मिला, तो यमन सरकार को सुन्नी बहुल सऊदी अरब का। 2015 में, विद्रोहियों ने पश्चिमी यमन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। तभी से, हमास और लेबनान के हिजबुल्ला के साथ हूती ने खुद को इस्राइल, अमेरिका व व्यापक पश्चिम के खिलाफ ईरानी नेतृत्व वाली 'प्रतिरोध की धुरी' का हिस्सा घोषित किया है। हालांकि हूती विद्रोहियों के ताजा हमले में कोई हताहत नहीं हुआ, पर इसके लगातार हमलों से यह साफ है कि पश्चिम एशिया में हिंसा के न रुकने का असर उससे सटे समुद्री मार्ग पर किस भयावह तरीके से पड़ रहा है। भारत का करीब 80 फीसदी व्यापार समुद्री रास्ते से होता है और 90 फीसदी ईंधन भी समुद्री मार्ग से ही आता है। चूंकि वैश्विक व्यापार का करीब 12 फीसदी हिस्सा लाल सागर से होकर गुजरता है, हूती विद्रोहियों के हमले का सीधा असर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ रहा है। हूती विद्रोही कह चुके हैं कि वे तब तक हमले जारी रखेंगे, जब तक कि इस्राइल गाजा में युद्ध समाप्त नहीं कर देता। लाल सागर मार्ग पर व्यापारिक जहाजों को सुरक्षा देने की अमेरिकी पहल के बावजूद हूती विद्रोहियों के हमले बढ़े हैं। ऐसे में, संयुक्त राष्ट्र समेत अमेरिका को चाहिए कि वे पश्चिम एशिया संकट हल करने की दिशा में कदम उठाएं, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी।

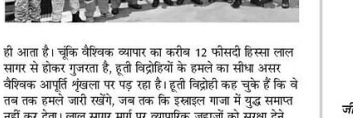

चुनाव, मजदूर और चिलचिलाती गर्मी

प्रचंड गर्मी से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर सबसे ज्यादा असुरक्षित होते हैं। लेकिन दुखद है कि लाखों भारतीयों के जीवन और आजीविका को प्रभावित करने वाला यह मुद्दा चुनावी चर्चा से बाहर है। सुरक्षा मानकों को लागू करने और श्रमिकों को मौसमी खतरों से बचाने के लिए मजबूत नियामक ढांचा जरूरी है।

भीषण गर्मी से झुलसते हुए जोधपुर में एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ने नगर निगम के सहयोग से अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वालों के लिए एक कूलिंग स्टेशन बनाया है। इस कूलिंग स्टेशन का उद्देश्य चिलचिलाती गर्मी में शहरी गरीबों को आश्रय देना है। यह जोधपुर के हीट ऐक्शन प्लान का हिस्सा है। दिलचस्प बात यह है कि इसमें ठंडक बढ़ाने के लिए पारंपरिक तरीकों को अपनाया गया है, जैसे खस से बने पैनल, सोलर पैनल से चलने वाले बल्ब और पंखे तथा फुहार के लिए स्प्रिंकलर। यहां पीने का पानी, प्राथमिक चिकित्सा (फर्स्ट एड) किट भी उपलब्ध है।

पत्रलेखा चटर्जी
वरिष्ठ पत्रकार

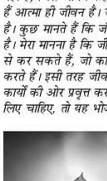

ऐसे समय में जब बड़े शहरों में रहने वाले लोगों सहित ज्यादातर भारतीय परिवारों के पास हर कमरे में एयर कंडीशनर (एसी) नहीं है, जोधपुर का यह प्रयोग बेहद दिलचस्प है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के दौर में अत्यधिक गर्मी, मौसम में उतार-चढ़ाव पूरे भारत और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में श्रमिकों की सुरक्षा के लिए वास्तविक खतरा है। ज्यादातर लोग इस भीषण गर्मी में एयरकंडीशनर का इंतजाम नहीं कर सकते। लेकिन दुर्भाग्य से भारत में यह अब भी चुनावी मुद्दा नहीं बन सका है, जबकि इसके प्रभाव स्पष्ट हैं। हाल में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के सहायक महानिदेशक और एशिया और प्रशांत क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक चिहोको असदा मियाकावा ने बताया कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में श्रमिकों को प्रचंड गर्मी से लेकर खराब वायु गुणवत्ता तक का सामना करना पड़ता है और इसके प्रभावों का खामियाजा भुगतना पड़ता है। अक्सर पर्याप्त सुरक्षा के बिना काम करते रहने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं होता, भले ही स्थितियां कितनी ही खतरनाक हों।

भीषण गर्मी शायद सबसे स्पष्ट चुनौती है और इस बारे में मियाकावा ने कहा कि बढ़ते तापमान में जैसे कृषि, निर्माण, मछली पकड़ने और परिवहन जैसे बाहरी काम करने वाले श्रमिकों को गर्मी से संबंधित

बीमारियों और लू का खतरा रहता है। यहां तक कि घर के अंदर काम करने वाले उन श्रमिकों को भी खतरा रहता है, जहां भीषण गर्मी हो और वेंटिलेशन की व्यवस्था न हो। फैक्टरियों, खाद्य प्रसंस्करण संयंत्रों, ईंट भट्ठों और गोदामों में तेज धूप के दौरान काम करना श्रमिकों के लिए काफी खतरनाक हो सकता है।

बेहतर नियमन, प्रवर्तन, शमन रणनीतियों, प्रशिक्षण और जागरूकता से स्थितियों में काफी बदलाव लाया जा सकता है। स्पष्ट है कि इसके लिए श्रमिकों का सशक्तीकरण जरूरी है, जो उन्हें नौकरी या मजदूरी खोने के डर के बिना प्रचंड गर्मी में काम रोकने की अनुमति प्रदान करे। लेकिन भारत जैसे देश में ऐसा कहना आसान है, करना कठिन, जहां ज्यादातर लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जिन्हें न तो रोजगार अनुबंध और न ही स्वास्थ्य संबंधी सहयोग उपलब्ध है।

मियाकावा लिखते हैं कि 'जलवायु परिवर्तन के कारण वायु प्रदूषण बढ़ने से श्वसन संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। बीजिंग, नई दिल्ली और बैंकॉक में खराब वायु गुणवत्ता दैनिक वास्तविकता है, जो प्रदूषकों के संपर्क में आने वाले श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य जोखिम पैदा करती है। आदर्श रूप में इन मूल कारणों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। डिलीवरी बॉय या सड़क के किनारे ठेला लगाने वाले को पूरे दिन जहरीली हवा में सांस लेना पड़ता है। इसलिए जागरूकता, रक्षा उपकरण और जहां तक संभव हो सके, काम करने के तरीके में बदलाव की आवश्यकता है, जो इसके प्रभाव को न्यूनतम कर सके।'

प्रचंड गर्मी और वायु प्रदूषण के अलावा, चरम मौसमी घटनाओं की आवृत्ति एवं तीव्रता में भी बढ़ोतरी हो रही है, जो कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए अतिरिक्त चुनौती पेश करती है। चक्रवात, बाढ़, सूखा, दावानल, प्राकृतिक आपदाएं कामकाज में व्यवधान पैदा करती हैं और श्रमिकों के जीवन को जोखिम में डालती हैं। मियाकावा लिखते हैं कि आपदाओं के बाद 'पहले की स्थिति की बहाली के प्रयासों में श्रमिकों की सुरक्षा एवं कल्याण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए तथा आवश्यक सेवाओं, सुरक्षात्मक उपकरणों और मनोसामाजिक समर्थन तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए।'

भारत विशेष रूप से संवेदनशील है। पिछले वर्ष फोर्ब्स मैगजीन ने लिखा था, 'निर्माण गतिविधियों के साथ भारतीय कृषि और उद्योग विशेष रूप से गर्मी से संबंधित तनावों के कारण श्रमिकों की उत्पादकता के नुकसान के प्रति संवेदनशील हैं। विश्व बैंक के अनुसार, 2030 तक गर्मी के तनाव के कारण उत्पादकता के नुकसान के चलते अनुमानित 8 करोड़ वैश्विक नौकरियों में से 3.4 करोड़ रोजगार की हानि भारत में हो सकती है।' फोर्ब्स मैगजीन में बताया गया कि 'रिजर्व बैंक के आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (डीईपीआर) ने मुद्रा एवं वित्त 2022-23 संबंधी अपनी नवीनतम रिपोर्ट में बताया कि भारत में बढ़ते तापमान और मानसूनी वर्षा के बदलते पैटर्न के कारण जलवायु परिवर्तन से अर्थव्यवस्था को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 2.8 प्रतिशत का नुकसान हो सकता है और 2050 तक भारत की लगभग आधी आबादी के जीवन स्तर में गिरावट आ सकती है। पर्याप्त शमन नीतियों के अभाव में जलवायु परिवर्तन से भारत को 2100 तक सालाना जीडीपी का लगभग 3 से 10 प्रतिशत तक का नुकसान हो सकता है।'

प्रचंड गर्मी से सभी समान रूप से प्रभावित नहीं होते हैं। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले, प्रवासी मजदूर और हाशिये पर रहने वाले लोग सबसे ज्यादा असुरक्षित होते हैं। महिलाएं भी व्यापक रूप से प्रभावित होती हैं। इसी वजह से हाइपर-लोकल ऐक्शन प्लान बनाना महत्वपूर्ण है, जो जोधपुर जैसे क्षेत्रों में कमजोर लोगों पर ध्यान केंद्रित करता है।

यह बेहद अफसोसनाक है कि लाखों भारतीयों के जीवन और आजीविका को प्रभावित करने वाले यह मुद्दा भारत की चुनावी चर्चा से बाहर है। लेकिन मतदान करते वक्त भारत के लोगों को उन उम्मीदवारों को ध्यान में रखना चाहिए, जो इन मुद्दों के प्रति संवेदनशील हैं और जिन्होंने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। जीडीपी में वृद्धि निस्संदेह महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय विमर्श को मजबूत नियामक ढांचे पर भी ध्यान देना चाहिए, जो सुरक्षा मानकों को लागू करने और श्रमिकों को जलवायु संबंधी खतरों से बचाने के लिए जरूरी हैं।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

पेरियार ई वी रामासामी

जीवन उस भोजन की देन है, जिसे हम ग्रहण करते हैं। यदि शरीर के अंगों को क्षति पहुंचे, तो जीवन ठहर जाता है। शरीर की सारी गतिविधियां शांत हो जाएंगी। इसलिए जहां चेतना है, उसे हम मनुष्य कहते हैं।

हम खुद को समझ लें तो ईश्वर को भी जान लेंगे

__जीवन__ आखिर है क्या? यह स्वयं एक विचार मात्र है। असल में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसे जीवन कहा जाए। कुछ कहते हैं, जीवन आत्मा है। कुछ कहते हैं आत्मा ही जीवन है। जबकि कुछ विद्वानों का मत है कि जीवन कुछ भी नहीं है। कुछ मानते हैं कि जीवन कुछ ऐसा है, जो आत्मनिर्भर होकर कार्य करता है। मेरा मानना है कि जीवन कोई वस्तु नहीं है। हम इसकी तुलना उस मशीन से कर सकते हैं, जो काम करती है और उसके चलने से बाकी हिस्से भी काम करते हैं। इसी तरह जीवन का काम है शरीर के दूसरे सभी हिस्सों को संबंधित कार्यों की ओर प्रवृत्त करना। यदि जीवन ऊर्जा है, जो लोगों को काम करने के लिए चाहिए, तो यह भोजन के समान है, जो शरीर को क्रियाशील बनाए रखने के लिए अत्यावश्यक है। यदि भोजन न मिले, तो शरीर का कोई अंग काम नहीं कर पाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जीवन उस भोजन की देन है, जिसे हम ग्रहण करते हैं। यदि शरीर के अंगों को किसी प्रकार की क्षति पहुंचे, तो जीवन ठहर जाता है। यदि भोजन न मिले, तब भी जीवन ठहर जाएगा। शरीर की सारी गतिविधियां शांत हो जाएंगी। इसलिए जहां चेतना है, उसे हम मनुष्य कहते हैं। यानी वही जीवन है।

चूंकि मनुष्य का जीवन ही ऐसा है कि वह व्यक्तिगत रूप से अपने सामान के बारे में बताने और उसकी ओर इंगित करने के योग्य होता है। दूसरे प्राणी भी अपने बारे में समझने की योग्यता रखते हैं। यदि आपके पास कुत्ता है, तो जब भी आप उसे उसके नाम से पुकारेंगे, तो वह आपकी ओर चला आएगा। इसी तरह दूसरे प्राणी भी अपनी चीजों की समझ रखते हैं। यदि आप किसी आदमी से पूछें कि उसके लिए जीवन या आत्मा का क्या अर्थ है, तो वह नहीं बता पाएगा। इसलिए कि वह उससे संबंधित वस्तु विशेष, अथवा उसके शरीर का कोई हिस्सा नहीं है। वह उन रासायनिक अभिक्रियाओं से अनजान है, जो उसके भीतर बदलाव का कारण बनती हैं और उसे वस्तु-जगत का अनुभव कराती हैं। यदि केसर और चूने को मिला दिया जाए, तो लाल रंग बन जाता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यौगिक जल कहलाता है। इसलिए जब हम कुछ पदार्थों को मिलते हुए देखते हैं, उस समय उनमें अनेक परिवर्तन होते हैं। यही परिवर्तन का प्राकृतिक नियम है, जिसे लोग भिन्न-भिन्न नामों से पुकारते हैं। मानव-शरीर में पाए जाने वाले ऐसे प्रबंध हमें विभिन्न कार्य करने का सामर्थ्य प्रदान करते हैं। यदि हम इसे समझ लें, तो हम जीवन या आत्मा को इतर वस्तु मानने से इन्कार कर देंगे। सामान्यतः आत्मा का संबंध केवल मनुष्यता से बताया जाता है, किसी प्राणी से नहीं। वेदों के अध्येता भी मानते हैं कि ईश्वर, आत्मा, जीवन तथा अन्य जीवित प्राणी मात्र अनुभूति हैं। वेद-विद्वान मानते हैं कि जो पहले स्वयं को जान लेता है, वह ईश्वर को समझने की योग्यता हासिल कर लेता है। यदि मनुष्य खुद को जान ले, तो वह ईश्वर को समझने की योग्यता पा लेता है।

निःस्वार्थ जीवन ही सर्वोत्तम...

सूत्र

मनुष्य अच्छे और बुरे, दोनों कर्मों से बंधा है। जब तक वह जीवित है, उसके कर्म अच्छे हो सकते हैं, और बुरे भी। ईश्वर, धर्म और आत्मा की खोज मानव जीवन को नियमित करने के लिए हुई है। इसके पीछे मनुष्य की सदेच्छा छिपी है। इसलिए मनुष्य को निःस्वार्थ जीवन जीना चाहिए।

दूसरा पहलू

कालबेलिया समुदाय घूम-घूमकर सांप पकड़ने के लिए विख्यात है और इसे सपेरा, जोगी या घुमंतू समुदाय भी कहा जाता है।

कालबेलिया समाज के सुरमे से नई पीढ़ी अनजान

आधुनिक काल में भी बहुत-से ऐसे समुदाय हैं, जिन्होंने अपनी संस्कृति और विरासत को आज भी मूल स्वरूप में बचाकर रखा है। इन्हीं में से एक राजस्थान का कालबेलिया समुदाय भी है, जो पीढ़ियों से देसी विधि से सुरमा (काजल) तैयार करता आ रहा है। इनका दावा है कि इस सुरमा के कारण ही इनके समुदाय में कभी किसी की आंखें खराब नहीं हुई हैं। घूम-घूमकर सांप पकड़ने के लिए विख्यात कालबेलिया समुदाय को सपेरा, जोगी या घुमंतू भी कहा जाता है, जो अपने नृत्य-संगीत के लिए भी मशहूर है।

घनश्याम सादावत

देसी सुरमा बनाने के लिए विख्यात यह समुदाय अपनी उत्पत्ति 12वीं सदी में गुरु गोरखनाथ के शिष्य से जोड़कर देखता है। सरकार से इसे अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है।

यह समुदाय अपनी उत्पत्ति 12वीं सदी में गुरु गोरखनाथ के शिष्य से जोड़कर देखता है। अधिकांश कालबेलिया खानाबदोश जीवन बिताते हैं। सरकार से इन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है। परंपरागत ज्ञान के कारण इन्हें स्थानीय वनस्पति और जीव-जंतुओं की खासी जानकारी होती है। इसी ज्ञान के आधार पर वे कई तरह के आयुर्वेदिक उपचार करते हैं। कालबेलिया जनजाति की सर्वाधिक आबादी राजस्थान के पाली जिले में है। अजमेर और इसके आसपास के गांवों में भी इनकी बड़ी आबादी पाई जाती है। देसी काजल के बारे में 80 वर्षीय बुजुर्ग बिदाम देवी कहती हैं कि 'सुरमा का प्रयोग समुदाय में जन्म लेने वाले बच्चे से लेकर 100 वर्ष के बुजुर्ग तक करते हैं। यह सुरमा शुद्ध देसी रूप से तैयार किया जाता है। इसे सांप का जहर, रतनजोत, समुद्री झाग, इलायची के बीज, पताल तुंबडी और बेल की जड़ आदि के मिश्रण से तैयार किया जाता है। इसे लगाते समय गुरुओं द्वारा बताए गए मंत्रों का जाप किया जाता है। हालांकि वह इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं देती हैं।' उनका कहना है कि 'पहले की अपेक्षा अब नई पीढ़ी सांप पकड़ने या गांव-गांव में सांप का खेल दिखाने की जगह व्यापार, दिहाड़ी मजदूरी, मार्बल फैक्टरियों में मजदूरी और गाड़ी चलाने जैसे कार्यों को प्राथमिकता देने लगी है।

नई पीढ़ी सांप पकड़ने या सांप का खेल दिखाने की जगह व्यापार, दिहाड़ी मजदूरी, मार्बल फैक्टरियों में मजदूरी और गाड़ी चलाने जैसे कार्यों को तवज्जो देने लगी है।

नई पीढ़ी के सांप पकड़ने से दूरी की एक वजह सांपों को लेकर सख्त वन्यजीव संरक्षण कानून भी है, जिसके तहत सांपों को रखने पर जेल या जुर्माने का प्रावधान है। कालबेलिया समाज की नई पीढ़ी भले ही देसी इलाज की जगह आधुनिक चिकित्सा को तरजीह देती हो, लेकिन बिदाम देवी जैसी बुजुर्ग अब भी अपने समाज की इस विरासत पर न केवल गर्व करती हैं, बल्कि वह इसे सहेज कर अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की जद्दोजहद भी करती नजर आ रही हैं। *(चरखा फीचर)*

आंकड़े

दुनिया का दवा घर

हाल में भारत से फार्मास्यूटिकल उत्पादों के निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, इसी वजह से भारत को 'दुनिया का दवा घर' कहा जाता है।

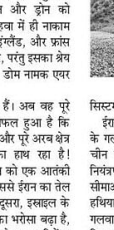

2022-23	1,56,401
2021-22	1,41,634
2020-21	1,41,207
2019-20	1,13,004
2018-19	1,00,682

आंकड़े करोड़ रुपये में | स्रोत : MoC&F

श्रद्धा और विश्वास के बिना मंत्र भी फल नहीं देते। इसलिए मंत्र सीखने से पहले श्रद्धा की साधना करनी चाहिए।

सिद्धि से पहले साधना

अंतर्यात्रा
संकलित

एक दिन राजा को कोई जरूरी मंत्रणा करनी थी, तो मंत्री को बुलवाया। मंत्री पूजा कर रहा था, इसलिए देर से आया। राजा ने जब देरी का कारण पूछा, तो उसने कहा, 'मैं गायत्री मंत्र जप रहा था। यह मंत्र लोक और परलोक में कल्याण के साधन जुटाता है। इसका फल बहुत बड़ा है।' राजा ने कहा–'तब तो इसे हम भी सीखेंगे।' मंत्री ने कहा, 'सीखने में हर्ज नहीं, पर आपको वैसा लाभ न मिल सकेगा, जैसा बताया गया है। श्रद्धा और विश्वास के बिना मंत्र भी फल नहीं देते। मंत्र सीखने से पहले श्रद्धा की साधना करनी चाहिए।'

राजा ने पूछा–'श्रद्धा के बिना मंत्र फल क्यों नहीं देता?' मंत्री ने कुछ उत्तर न दिया, चुप हो गए। थोड़ी देर में एक बालक से मंत्री ने कहा-'राजा के गाल पर एक चपत लगा दो।'

बालक यह सुनकर सन्न रह गया, पर उसने वैसा किया नहीं। राजा को क्रोध आ गया और उसने लड़के को कहा कि मंत्री के गाल पर दो चपत लगाओ। लड़के ने तुरंत मंत्री के गाल पर दो चपत जड़ दिए। मंत्री ने कहा, 'राजन, यह आपके प्रश्न का उत्तर है। लड़के ने मेरा कहना नहीं माना, क्योंकि इसने आपको वैसी आज्ञा के योग्य और मुझे अयोग्य माना। मंत्रों की भी यही बात है। वे श्रद्धावान व सत्पात्र की ही इच्छा पूरी करते हैं।' *(अमर उजाला आर्काइव से)*

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 3 जनवरी, 1960

वीपी मेनन के खिलाफ मानहानि का दावा

श्री वी० पी० मेनन पर मानहानि का दावा

हिंदू महासभा के भूतपूर्व अध्यक्ष एवं वायसराय की कार्यकारिणी के पूर्व सदस्य डॉ खरे ने केंद्र सरकार के रियासती विभाग के पूर्व सचिव एवं स्वतंत्र पार्टी के नेता वीपी मेनन के विरुद्ध अदालत में मानहानि का दावा पेश किया है।

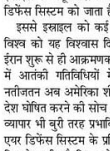

इस्राइल की तरह अभेद्य भारतीय सुरक्षा

जैसे इस्राइल ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से ईरानी हमले को नाकाम किया, ठीक वैसी ही अभेद्य सुरक्षा तैयारी चीनी सीमा पर भारत ने भी की है।

शिवदान सिंह | रक्षा

पिछले दिनों ईरान ने इस्राइल पर 120 मिसाइल तथा 300 ड्रोन से हमला किया, परंतु ईरान के 99 फीसदी मिसाइल और ड्रोन को इस्राइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नाकाम कर दिया! हालांकि इसमें अमेरिका, इंग्लैंड, और फ्रांस इत्यादि देशों ने भी उसकी मदद की थी, परंतु इसका श्रेय इस्राइल के अनूठे रक्षा कवच आयरन डोम नामक एयर डिफेंस सिस्टम को जाता है।

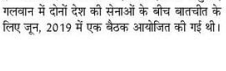

इससे इस्राइल को कई लाभ हुए हैं। अब वह पूरे विश्व को यह विश्वास दिलाने में सफल हुआ है कि ईरान शुरू से ही आक्रमणकारी रहा है और पूरे अरब क्षेत्र में आतंकी गतिविधियों में ईरान का हाथ रहा है! नतीजतन अब अमेरिका शीघ्र ही ईरान को एक आतंकी देश घोषित करने की सोच रहा है, जिससे ईरान का तेल व्यापार भी बुरी तरह प्रभावित होगा! दूसरा, इस्राइल के एयर डिफेंस सिस्टम के प्रति दुनिया का भरोसा बढ़ा है, जिससे उम्मीद है कि उसके आयरन डोम एयर डिफेंस

सिस्टम के लिए कई देशों से ऑर्डर मिल सकते हैं।

ईरान जैसी ही हरकत चीन ने भी 2019 में लद्दाख के गलवान में की थी! दरअसल 1996 में भारत और चीन के बीच हुए समझौते के अनुसार, वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएससी) के पास नोमैंस लैंड या सीमाओं के मध्यवर्ती क्षेत्र में दोनों देशों के सैनिक बगैर हथियारों के ही गश्त करेंगे! इसी समझौते के अनुसार, गलवान में दोनों देश की सेनाओं के बीच बातचीत के लिए जून, 2019 में एक बैठक आयोजित की गई थी। इसमें हिस्सा लेने भारतीय सैनिक तो बगैर हथियारों के पहुंचे, लेकिन चीनी सैनिक कंटीले तार लगे लाठी-डंडों के साथ आए और बिना किसी उकसावे के उन्होंने भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया। मगर निहत्थे भारतीय सैनिकों ने बहादुरी से इसका जवाब देते हुए कई चीनी सैनिकों को ढेर कर दिया तथा सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पहाड़ियों पर भी कब्जा कर लिया। अब इस क्षेत्र में चीन आसानी से घुसपैठ नहीं कर सकेगा!

चीनी हमले का वही परिणाम हुआ, जैसा कि इस्राइल पर ईरान के हमले का हुआ है। इससे चीनी सैनिकों की साख पर भारी धब्बा लगा है। इस्राइल को ईरान के हमले को नाकाम करने से जो उपलब्धियां हासिल हुई हैं, वहीं लाभ भारत को भी मिला था।

भारत ने गलवान हमले के बाद चीनी सीमा पर अपनी रक्षा तैयारी पर और जोर देना शुरू कर दिया है! भारत ने चीनी सीमा पर हवाई सुरक्षा को इस्राइल की तरह अभेद्य बनाने के लिए लद्दाख के पास नियोमा में नए हवाई अड्डे का निर्माण किया है! इसके अलावा, दौलत बेग ओल्डी नामक हवाई पट्टी का भी विस्तार किया गया है। इन दोनों स्थानों से अब राफेल जैसे लड़ाकू विमान उड़ान भर सकते हैं! हवाई हमले की पूर्व सूचना देने के लिए भारत ने आकाशतीर नामक एयर डिफेंस सिस्टम को भी चीनी सीमा पर तैनात कर दिया है! आधुनिक तकनीक से निर्मित इस सिस्टम की सूचना के आधार पर दुश्मन के हवाई जहाज या मिसाइलों को गिराने के लिए आकाश मिसाइल की यूनिट तैनात की गई है! यह मिसाइल लेजर सिस्टम से नियंत्रित होती है, जिसे लक्ष्य से भटकाना असंभव है।

इनके अतिरिक्त, दुश्मन पर मिसाइल से हमला करने के लिए आईजीएलए नाम की मिसाइल के 120 लॉन्चर भी चीन सीमा पर तैनात किए गए हैं। 1,000 आधुनिक ड्रोन किसी भी खतरे से मुकाबले के लिए हमेशा तैयार रहते हैं! यही नहीं, लद्दाख तथा अरुणाचल प्रदेश में जमीनी युद्ध के लिए आर्म्ड कोर की टैंक यूनिटों को भी तैनात किया गया है। सेना की स्ट्राइक कोर, जिसमें लड़ाकू टैंक यूनिटों के साथ करीब 15,000 सैनिक होते हैं, को भी अरुणाचल में स्थापित कर दिया गया है!

सीमा पर शीघ्र सैन्य सहायता तथा रसद पहुंचाने के लिए अरुणाचल की सीमा तक कई पुलों तथा सड़कों का निर्माण किया गया है! यहीं पर बीते मार्च में प्रधानमंत्री मोदी ने सेलापास नामक सुरंग का उद्घाटन किया। 2010 से पहले लेह को भारत से जोड़ने के लिए केवल एक सड़क श्रीनगर–लेह थी ! अब लेह को एक और लंबी सुरंग द्वारा हिमाचल प्रदेश से भी जोड़ दिया गया है। हिमाचल वाला मार्ग बहुत सुरक्षित है, जिस तक पाकिस्तान पहुंचने की सोच भी नहीं सकता! इस प्रकार अरुणाचल प्रदेश और लेह-लद्दाख के लिए संचार व्यवस्था और सड़क मार्गों की व्यवस्था से इन स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था और भी मजबूत हो गई है। भारत की इन रक्षा तैयारियों को देखकर अब चीन भारत पर कुदृष्टि डालने की सोच भी नहीं सकता!

जीवन दर्शन

ब्रह्मा कुमारी शिवानी
प्रेरक वक्ता

आत्म-परमात्म योग

हम शाश्वत प्रेम के अर्थ को जानें तथा अपनी दृष्टि, वृत्ति, रुचि, स्नेह और श्रद्धा को बाह्य तत्वों से आत्मिक सत्यों की ओर मोड़ें अर्थात अपने मन, बुद्धि एवं भावनाओं को स्नेह स्वरूप अंतरात्मा की ओर ले चलें और इन्हें शाश्वत प्रेम के सागर परमात्मा के साथ जोड़ें...

मूल रूप में हम आत्मा हैं। प्रेम स्वरूप हैं। इस सत्य स्वरूप या आत्मिक स्थिति में स्थित होकर हम असीम प्रेम व स्नेह की ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। प्राणी, प्रकृति और पूरी सृष्टि के साथ अपने संबंधों को हम मधुर व स्नेहसंपन्न बना सकते हैं। आवश्यकता यह है कि हम शाश्वत प्रेम के अर्थ को जानें, उसकी परिभाषा समझें तथा अपनी दृष्टि, वृत्ति, रुचि, स्नेह और श्रद्धा को बाह्य तत्वों से आत्मिक सत्यों की ओर मोड़ें अर्थात अपने मन, बुद्धि एवं भावनाओं को निर्मल स्नेह स्वरूप अंतरात्मा की ओर ले चलें और इन्हें शाश्वत प्रेम के सागर परमात्मा के साथ जोड़ें। इस आत्म-परमात्म योग के बाद हमें प्रेम की भावनाओं को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हमारी पूरा जीवन ही प्रेममय हो जाएगा।

वस्तुतः हम अपने आप में प्रेम ही हैं और हमारा सत्य स्वरूप और स्वाभाविक स्वभाव भी प्रेम ही है। लेकिन, हमारे अंदर का असुरक्षा भाव, दूसरों के प्रति दोष-दृष्टि, क्रोध, प्रतिस्पर्धा, अपमान या आहत होने की भावनाएं हमारे असीम प्रेम के निर्मल प्रवाह को बाधित कर देती हैं। अंदर का व्यर्थ, अस्वस्थ एवं नकारात्मक सोच स्नेह की कोमल भावनाओं का दमन कर देता है। प्रेम के स्वच्छ और शाश्वत स्रोत में अवरोध उत्पन्न करता है।

आज सच्चा प्रेम पाने या अनुभव करने के लिए हम किसी अन्य पर आश्रित हो जाते हैं, क्योंकि आत्मिक स्नेह का मूल अंतरात्मा से तथा प्रेम के शाश्वत स्रोत परमात्मा से हमारे मन, बुद्धि व भावनाओं का नाता टूट गया है। इसलिए अगर हम अपने से या दूसरों से अहैतुक प्रेम पाना चाहते हैं, तो हमें भी उन्हें बिना किसी शर्त प्यार देना होगा। इसके लिए हमें अपने सत्य स्वरूप को जानना होगा, साथ ही दूसरों की भावनाओं और अपेक्षाओं को भी महसूस करना होगा। अक्सर प्रेम को कुछ नकारात्मक संवेदनाओं, जैसे-मोह, अपेक्षा, चिंता, तनाव, भय या क्रोध की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है, जो ठीक नहीं है। मोह या आसक्ति हमें शक्तिहीन करता है, जबकि सच्चा प्रेम शक्तिशाली बनाता है।

वर्तमान में संबंधों में टकराव का मूल कारण लोगों का दृष्टिकोण एवं भौतिकवादी मानसिकता है, जिसके कारण कुछ जगह जाति, धर्म, वर्ण, भाषा, प्रांत आदि के आधार पर भेदभाव और अनैतिक आचरण होता है। ऐसे वातावरण को जीवन अनुकूल बनाने की आवश्यकता है। इस बदलाव की प्रक्रिया में सर्वप्रथम मानवीय सोच, विचार, भावना, दृष्टि, वृत्ति, कर्म, व्यवहार, संस्कार और संबंधों में सुधार लाने की आवश्यकता है। इस सुधार की आधारशिला के रूप में जीवन में सत्यबोध, आत्मबोध व आत्मिक प्रेम की आवश्यकता है।

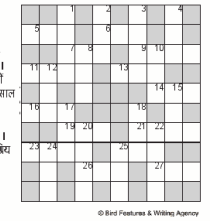

पूरी मानवता आज क्षणभंगुर इंद्रियभोग और दैहिक प्रेम से ऊब चुकी है। मानव को आत्मिक प्रेम व सहयोग की आवश्यकता है। आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग ध्यान-अभ्यास की प्रक्रिया से हम सही सोचने, समझने, परखने और निर्णय लेने की आंतरिक शक्ति विकसित कर पाएंगे। इस आध्यात्मिक ज्ञान से हमारे संपर्क में आने वाले जो लोग हैं, जैसे हैं, उनको हम बिना किसी शर्त, बिना किसी तुलना या अपेक्षा के सहज ही स्वीकार कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में समाज के प्रति हम अपने अहैतुक प्रेम को प्रकट व संचारित कर सकते हैं। हमें ईश्वर के समान प्रेम-स्वरूप की मनोस्थिति में रहना होगा, तब हमारी दृष्टि में संपूर्ण जगत सुखदाई, भावपूर्ण व प्रेममय हो जाएगा।

लेख विस्तार से पढ़ने के लिए स्कैन करें।

आध्यात्मिक ज्ञान से जागता है प्रेम

सच्चा प्रेम कोई बाहरी स्थूल वस्तु नहीं है, जिसे जब चाहे खरीदा या बेचा जा सके या उपयोग कर त्याग किया जा सके। सच्चा प्रेम तो हमारी अपनी प्रकृति के रूप में हमारे अंदर निहित है। उसे मात्र आध्यात्मिक ज्ञान और योग बल से जगाने की देरी है। निश्छल प्रेम वास्तव में स्वयं और सबके प्रति समानतापूर्वक आत्मिक स्नेह, दया, करुणा, सहानुभूति और संवेदनशीलता भरी शुभभावना व शुभकामनाओं से प्रस्तुत होने की सहज, सरल और पवित्र मानसिकता है। शाश्वत प्रेम तो स्वयं को तथा औरों को बिना किसी शर्त या पूर्वाग्रह के समझने, समझाने, सहने, स्वीकारने एवं सराहने की आध्यात्मिक अभिव्यक्ति है।

चिंतन धरोहर

स्वामी रामकृष्ण परमहंस

बनें ईश्वर का दास

अहंकार दो प्रकार का होता है। एक है पक्का 'मैं' और दूसरा कच्चा 'मैं'। 'जो कुछ भी है, उसमें कुछ भी मेरा नहीं है। यह शरीर भी मेरा नहीं है। मैं नित्यमुक्त हूं, मैं ज्ञानस्वरूप हूं।' यह पक्का 'मैं' है। 'मैं प्रभु का दास हूं'-यह विद्या का 'मैं' है, जिसे पक्का 'मैं' कहा जाता है। 'यह मेरा लड़का है, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा शरीर है' यह कच्चा मैं है। जो 'मैं' मनुष्य को संसारी बनाता है, कामिनी-कांचन में आबद्ध करता है, वह कच्चा 'मैं' है। जीव और ब्रह्म में भेद बस इसलिए है कि उनके बीच में यह 'मैं' खड़ा हुआ है। पानी पर एक लाठी डाल दी जाए तो पानी दो भागों में बंटा हुआ सा दिखाई पड़ता है। 'अहंकार' या 'मैं' ही यह लाठी है, इसे उठा लो तो जल एक ही रह जाएगा।

'मैं' को दूर करना कठिन है। इस कारण अपने 'मैं' से यह कहना चाहिए कि तू ईश्वर का दास बनकर रह। मैं ईश्वर का दास हूं, भक्त हूं- ऐसे भाव में रहो, तो दोष नहीं। यह पक्का 'मैं' भक्तिपथ पर आगे बढ़ने का सूचक है। इसके द्वारा ईश्वर लाभ होता है। ईश्वर प्राप्ति के पश्चात 'दास मैं' या 'भक्त मैं' किसी का अनिष्ट नहीं कर सकता। पारस पत्थर को छूने पर तलवार सोना बन जाती है, तलवार का आकार तो रहता है, पर वह किसी को हत नहीं कर सकती।

अगले मंगलवार को पढ़ें श्री श्री रविशंकर का चिंतन

सप्ताह के व्रत त्योहार

30 अप्रैल, मंगलवार : श्री गुरु अर्जुनदेव जयंती
एक मई, बुधवार : शीतलाष्टमी व्रत
चार मई, शनिवार : श्री वल्लभाचार्य जयंती,
पांच मई, रविवार : प्रदोष व्रत।

वर्ग पहेली-2616

बाएं से दाएं
5 सुगंधित, खुशबूदार (3)। 6 आनंद, दशा (3)। 7 दुर्दशा, आफत (3)। 9 नमकीन, लवण-संबंधी (4)। 11 आधा कच्चा (4)। 13 बिना नाम वाला, जिसे कोई नहीं जानता हो (3)। 14 उदाहरण, मिसाल (3)। 16 बैलगाड़ी, छकड़ा (3)। 19 गबन, पाचनक्रिया (3)। 21 शरीर पर मलने योग्य लेप (4)। 23 कहने योग्य (4)। 25 किसी प्रिय के अलगने का संताप (3)। 26 सुर, भगवान (3)। 27 पंकज, सरोज, अरविंद (3)।

ऊपर से नीचे
1 झूठा दोष, कोसना, शाप (4)। 2 झटपट, जल्दी, शीघ्र (3)। 3 समझाना-बुझाना (4)। 4 सुनना (3)। 8 रहने का घर (3)। 10 उल्टी, कै (3)। 12 आंच की भड़क, लौ, (3)। 15 सहसा, जिगरा (3)। 17 शाखा, डाली (3)। 18 किसी काम को करने का सुंदर ढंग, सलीका (3)। 20 गीत-गोविंद के रचनाकार (4)। 22 मार्गभ्रष्ट होना, भटकना (4)। 24 तमाचा, चांटा, चमेटा (3)। 25 विस्तार, फैलाव, समूह (3)।

© Bird Features & Writing Agency

कल का हल

आ	तु	र	ता				सि	या	र
नं			म	ल	या	ल	म		ख
द	र	बा	र				ट		वा
	क्षा		स	र्प		आ	न	भ	ला
	बं					जा		यं	
	ध		चा					क	
ब	न	जा	रा		वा	म		र	
न		ल				ह	ड़	ता	ल
वा		सा	र्व	का	लि	क			व
स	मा	ज				नी	रा	य	ण

जागरण सुडोकू-2616

	9			8			7	
		6		3			2	
7	3		6		5	8		9
	8							2
2			8		1		9	
		1			4			6
6				7			3	
	7	9		4		2		8
4							5	

कल का हल

1	8	5	9	3	7	4	6	2
4	2	7	6	5	8	9	1	3
9	6	3	2	4	1	7	5	8
3	1	2	7	8	4	5	9	6
8	5	9	3	1	6	2	7	4
7	4	6	5	2	9	3	8	1
6	7	4	8	9	2	1	3	5
2	3	8	1	7	5	6	4	9
5	9	1	4	6	3	8	2	7

आज का भविष्यफल- 30 अप्रैल, 2024 मंगलवार

के.ए. दुबे पद्मेश

आज की ग्रह स्थिति : वैशाख मास कृष्ण पक्ष षष्ठी। आज का राहुकाल : अपराह्न 03 बजे से 04 बजकर 30 मिनट तक। आज का दिशाशूल : उत्तर। आज की भद्रा : प्रातः 07 बजकर 06 मिनट से सायं 06 बजकर 26 मिनट तक।

कल 01 मई, 2024 का पंचांग
कल का दिशाशूल : उत्तर।
कल का पर्व एवं त्योहार : शीतलाष्टमी।
विशेष : अष्टमी तिथि क्षय, गुरु वृष राशि में एवं श्रमिक दिवस।
विक्रम संवत 2081 शके 1946 उत्तरायण, उत्तरगोल, वसंत ऋतु, वैशाख मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तत्पश्चात अष्टमी, श्रवण नक्षत्र तत्पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र, शुभ योग तत्पश्चात शुक्ल योग, मकर में चंद्रमा।

मेष : गुरु का परिवर्तन और शुक्र का अस्त होना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है।
वृष : आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, लेकिन स्वास्थ्य प्रभावित होगा।
मिथुन : गुरु व्यावसायिक और पारिवारिक मामलों में समस्याएं देंगे।
कर्क : मांगलिक योजना साकार होगी, लेकिन निजी सुख में व्यवधान आएगा।
सिंह : पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि। रचनात्मक कार्यों मे सफलता मिलेगी।
कन्या : आर्थिक मामलों में सफलता देगा। निजी सुख में वृद्धि कराएगा।
तुला : स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा। अध्यात्मिक ऊर्जा में वृद्धि होगी।
वृश्चिक : दांपत्य जीवन में चली आ रही समस्याओं का समाधान होगा।
धनु : रोग और विरोधी तनाव देंगे। कार्य क्षेत्र में व्यवधान मिल सकता है।
मकर : गुरु का परिवर्तन संतान की प्रगति में सहायक होगा।
कुंभ : निजी सुख व संपत्ति में वृद्धि। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें।
मीन : पुरुषार्थ सार्थक होगा। आर्थिक मामलों में प्रगति होगी।

दर्शन परंपरा

डा. चिन्मय पण्ड्या
प्रतिकुलपति, देवसंस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार

पुष्टिमार्ग के प्रवर्तक श्री वल्लभाचार्य

महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का अवतरण उनके पूर्वजों द्वारा पांच पीढ़ियों तक सौ सोमयज्ञ पूर्ण करने के उपरांत हुआ था। उनका जन्म विक्रम संवत 1535 में दक्षिण के उत्तरादि (वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर) में तैलंग ब्राह्मण परिवार में पिता लक्ष्मण भट्ट और माता श्रीइलम्मा के घर द्वितीय पुत्र के रूप में हुआ। भागवत प्रेमियों और सुसंस्कारित परिवार में बचपन बीता और उन्होंने काशी के प्रकांड विद्वान माधवेंद्र पुरी से वेद-शास्त्र का अध्ययन मात्र 11 वर्ष की आयु में कर लिया।

वेदांत के संप्रदायों में वल्लभ संप्रदाय अपनी अलग विशेषता रखता है। वल्लभाचार्य जी ने विशेष सिद्धांतों की नींव पर वैष्णव संप्रदाय का भवन खड़ा किया। उन्होंने वेदांत सूत्रों को लेकर अणुभाष्य किया और श्रीमद्भगवद्गीता को लेकर सुबोधिनी तथा अनेक ग्रंथों व सूत्रों की रचना कर शुद्धाद्वैत के सिद्धांतों की व्याख्या की। भक्ति संप्रदाय में इसे पुष्टिमार्ग के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि प्रभु की भक्ति तब पूरी होती है, जब साधक का तन, मन और हृदय उनमें समर्पित हो अर्थात पूर्ण समर्पण के साथ प्रभु की भक्ति करने से ही ईश्वरीय कृपा की प्राप्ति होती है।

श्री वल्लभाचार्य ने वृंदावन में रहकर भगवान श्रीकृष्ण के बालस्वरूप की प्रेममयी आराधना की। इनकी अष्टयाम सेवा बड़ी ही सुंदर है। इसमें माधुर्यभाव है। गृहस्थाश्रम में रहते हुए वल्लभाचार्य जी ने भगवान श्रीकृष्ण की वात्सल्य भाव से उपासना की। वल्लभाचार्य जी की भक्ति और व्यक्तित्व का लोगों पर इतना विलक्षण प्रभाव पड़ा कि अनेकानेक लोग श्रीकृष्ण के बालस्वरूप के प्रेमी बन गए। उन्होंने भक्तिकाल के कवि सूरदास जी को प्रभु की लीलाओं से परिचित करवाया और लीलागान हेतु प्रेरित किया, जिसके कारण आज हम लीलाधर श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं से परिचित हैं। वल्लभाचार्य जी ने अनेक भाष्य, ग्रंथ, नामावलियां, स्तोत्र आदि की रचना की। उनकी प्रमुख 16 रचनाओं को षोडश ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। इनके नाम हैं-यमुनाष्टक, बालबोध, सिद्धांत मुक्तावली, पुष्टि प्रवाह-मर्यादा भेद, सिद्धांत रहस्य, नवरत्न स्तोत्र, अंतःकरण प्रबोध, विवेक धैर्याश्रय, श्रीकृष्णाश्रय, चतुःश्लोकी, भक्तिवर्धिनी, जलभेद, पंचपद्यानि, संन्यास निर्णय, निरोध लक्षण, सेवाफल।

चार मई को है श्री वल्लभाचार्य की जयंती

भारत में भक्ति की अविरल धारा शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, आचार्य निंबार्क और वल्लभाचार्य से लेकर अब तक बहती चली आ रही हैं। वल्लभाचार्य कृष्ण भक्ति शाखा के वह आधार स्तंभ हैं, जिन्होंने साधना के लिए पुष्टिमार्ग से परिचित करवाया, जिन्होंने सूरदास को पुष्टिमार्ग का जहाज बनाया। पुष्टिमार्ग के इस प्रवर्तक ने संपूर्ण समाज को भक्ति मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया और मानव जीवन को प्रभु की शरण में लीन करने के लिए मार्गदर्शन किया। वर्तमान समय में जिस तरह मानव में वैचारिक दुष्प्रवृत्तियां पनपी हैं, इसका एकमात्र कारण ईश्वर के बनाए आदर्शों से विमुख होना है।

राष्ट्रीय जागरण

सूर्य के पहलू में छिपने जा रहा सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति

नासा की अंतरिक्ष दूरबीन हबल से ली गई बृहस्पति की तस्वीर। ●सौ. इंटरनेट मीडिया

रमेश चंद्रा ● नैनीताल

हमारे सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति (जुपिटर) सूर्य के पहलू में छिपने जा रहा है। 18 मई को होने जा रही युति यानी कंजक्शन की इस खगोलीय घटना के दौरान बृहस्पति करीब चार सप्ताह तक यह पृथ्वी से नजर नहीं आने वाला है।

इस अवधि में बृहस्पति ग्रह पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर भी रहेगा। नैनीताल स्थित आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान के खगोल विज्ञानी डा. शशिभूषण पांडेय के अनुसार बृहस्पति अपने पथ पर अब सूर्य के करीब से गुजरने जा रहा है। इस दौरान बृहस्पति की कक्षा पृथ्वी से सौर मंडल के सुदूर हिस्से में होगी, जो कि सूर्य के बिलकुल पीछे होगी। जिस कारण पृथ्वी से बृहस्पति नजर ही नहीं आएगा। इसके साथ-साथ वह सूर्य के नजदीक होने के कारण उसकी रोशनी में भी खोया रहेगा। यह स्थिति 18 मई से शुरू होकर करीब चार सप्ताह तक रहेगी। इस दौरान बृहस्पति पृथ्वी से सर्वाधिक दूर और सूर्य के सबसे नजदीक पहुंच जाएगा। सूर्य व बृहस्पति के बीच आभासीय दूरी मात्र 0.43 डिग्री रह जाएगी। इसी समय बृहस्पति व पृथ्वी की दूरी 6.03 एयू (खगोलीय इकाई) हो जाएगी। एक खगोलीय इकाई 15 करोड़ किमी की होती है। डा. पांडेय के अनुसार, बृहस्पति व सूर्य की युति यानी कंजक्शन लगभग 12 वर्ष में एक बार होती है।

वाराणसी समेत देश के 30 हवाई अड्डों को बम से उड़ाने की धमकी

जासं, वाराणसी : जयपुर, नागपुर, कानपुर, वाराणसी सहित देश के 30 हवाईअड्डों को बम से उड़ाने की धमकी का ईमेल मिला है। वाराणसी एयरपोर्ट के निदेशक पुनीत गुप्ता को सोमवार को भेजे गए ईमेल में लिखा है कि हमने सभी 30 एयरपोर्ट पर बम लगा दिया है और रिमोट का बटन दबाते ही उनमें धमाका हो जाएगा। इसके बाद हाईअलर्ट जारी करते हुए आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें सीआइएसएफ, कमिश्नरेट पुलिस समेत खुफिया एजेंसियों के अधिकारी शामिल हुए।

गोरखपुर में दर्ज था हत्या का केस, 15 माह बाद लौटीं बहनें

- दोनों ने हरियाणा में भिवानी और उत्तराखंड में रहने वाले प्रेमी से कर लिया है विवाह
- दिल्ली में रहने वाले भाई ने बेलघाट थाने में दर्ज कराया था हत्या का केस

जागरण संवाददाता, गोरखपुर : दिल्ली के प्रेमनगर में रहने वाली बहनों ने हरियाणा व उत्तराखंड के अपने प्रेमियों संग शादी कर ली और घरवालों ने शक के आधार पर गोरखपुर, बेलघाट के युवक और उसके स्वजन पर हत्या कर साक्ष्य मिटाने का मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस की छानबीन में पता चला कि दोनों जिंदा हैं।

सोमवार को बेलघाट थाने पहुंचकर दोनों बहनों ने जिंदा होने का प्रमाण देने के साथ ससुराल में राजी खुशी रहने की बात कही। युवतियों का बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने दोनों को पति के साथ भेज दिया। बेलघाट के श्यामसुंदर परिवार के साथ दिल्ली के प्रेमनगर में रहते थे। तीन जनवरी, 2023 को उनकी दोनों बेटियां गायब हो गईं। श्यामसुंदर के बेटे ने गांव के ही जयनाथ मौर्य पर बहनों का अपहरण कर हत्या करने का संदेह जताया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आठ जनवरी, 2024 को जयनाथ मौर्य व स्वजन के विरुद्ध दोनों बहनों की हत्या और शव जलाने का मुकदमा किया। सर्विलांस की मदद से पता चला कि गीता ने उत्तराखंड के चमोली के द्रमोली गांव के युवक से शादी कर ली है। उनकी छह माह की बेटी भी है। दूसरी बहन ने हरियाणा के भिवानी में भवानी खेड़ा केभैइनी ठाकरान गांव के विजेन्दर से विवाह कर लिया है। उसकी भी पांच माह की एक बेटी है। विवेचक ने बेलघाट थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज होने की जानकारी दी तो दोनों ने बताया कि उन्होंने मर्जी से विवाह किया है। विवेचक के बुलाने पर दोनों ने सोमवार को बेलघाट थाने पहुंचकर बयान दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि जयनाथ मौर्या दिल्ली में घर आता था। इसी वजह से भाई ने हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया।

ट्रेन में खानपान का ठेका लेंगी कंपनियां, बेस किचन भी बनाएंगी

निशांत यादव ● जागरण

- रेलवे बदलने जा रहा है खानपान नीति, जून तक पूरी होगी नई टेंडर प्रक्रिया भी
- नहीं होंगी यशवंतपुर-गोरखपुर एक्सप्रेस का खाना खाकर बीमार होने जैसी घटनाएं

> रेलवे यात्रियों को अब बेस किचन से तैयार खाना मिलेगा। यह बेस किचन खानपान का लाइसेंस लेने वाली कंपनियां बनाएंगी। रेलवे बोर्ड स्तर पर कुछ बदलाव किए जा सकते हैं।
>
> **अजीत कुमार सिन्हा,** मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक, आइआरसीटीसी

लखनऊ: पिछले दिनों यशवंतपुर-गोरखपुर सुपरफास्ट ट्रेन में रसोई यान न होने की कीमत कई यात्रियों को चुकानी पड़ी। अवैध वेंडरों ने ट्रेन में अंडा करी व अंडा बिरयानी बेची, जिससे तमाम यात्री बीमार हो गए। अब ट्रेनों में अवैध वेंडिंग रोकने व यात्रियों को अच्छा खाना उपलब्ध कराने के लिए रेलवे बोर्ड नई खानपान नीति लागू करने जा रहा है। अब ट्रेनों के रसोई यान का लाइसेंस कंपनियों को सात वर्षों के लिए मिलेगा। इससे कंपनियां अपना बेस किचन भी तैयार करेंगी। जून में चुनाव आचार संहिता हटते ही रसोई यान के लाइसेंस नए नियम के तहत देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

रेलवे में यात्रियों को खानपान सुविधा उपलब्ध कराने की दो तरह की विभागीय व्यवस्था लागू हैं। शताब्दी एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस और राजधानी एक्सप्रेस सहित प्रीमियम ट्रेनों में किराये के साथ ही खानपान चार्ज यात्रियों से जमा कराया जाता है। यह खानपान की प्रीपेड व्यवस्था है। इसके अलावा आइआरसीटीसी के वेंडर चलती ट्रेन में यात्रियों को खाना उपलब्ध कराने के बाद उनसे उसकी कीमत लेते हैं। यह पोस्टपेड सुविधा है। प्रीमियम ट्रेनों का प्रीपेड खाना तो कुछ ठीक भी है, लेकिन शिकायत पोस्टपेड सुविधा वाली ट्रेनों में आ रही हैं। इसके पीछे रेलवे की खानपान नीति की कमी एक मुख्य कारण है। अभी तीन-तीन माह का लाइसेंस वेंडरों को दिया जा रहा है। ऐसे में अपने खानपान की गुणवत्ता को सुधारने के लिए उनमें रुचि नहीं दिख रही है। रेलवे की वर्ष 2017 की खानपान नीति में बेस किचन बनाने का प्रविधान किया गया था, लेकिन लीज पालिसी की बाधा के कारण बेस किचन के लिए जगह का आवंटन फंस गया।

अब होंगे ये बदलाव : ट्रेनों में खानपान का लाइसेंस लेने वाली कंपनियों को सात वर्ष का ठेका मिला तो ये कंपनियां निवेश भी करेंगी। इन कंपनियों को बड़े रेलवे स्टेशनों के परिसर या उस शहर में आइआरसीटीसी के तय मानकों के तहत खाना तैयार करना होगा। बेस किचन से ही तैयार खाना प्रीमियम और अन्य ट्रेनों के यात्रियों को मिलेगा। बेस किचन में तैयार खाने की गुणवत्ता की मानीटरिंग उस क्षेत्र के आइआरसीटीसी के अधिकारी करेंगे।

समिति ने की थी सिफारिश : संसद की लोक लेखा समिति ने इस वर्ष फरवरी में भारतीय रेलवे ने खानपान सेवा नाम से अपनी रिपोर्ट में कहा था कि वर्ष 2005, 2010 और 2017 में खानपान नीति में हुए बदलाव के कारण ट्रेनों के खानपान में सुधार नहीं हो सका है। समिति ने खानपान नीति में स्थिरता लाने का सुझाव दिया है। बदलाव से कैटरिंग कंपनियां लंबे समय के लिए निवेश से बचती हैं, जिसका असर खानपान की गुणवत्ता पर पड़ता है।

मनोरंजन

'खेल खेल में' फिल्म में अक्षय कुमार, वाणी कपूर, तापसी पन्नू, आदित्य सील, फरदीन खान, प्रज्ञा जायसवाल और एमी विर्क अहम भूमिकाओं में हैं ● @adityaseal (इंस्टाग्राम)

शेड्यूल से पहले ही खत्म हो गई 'खेल खेल में' की शूटिंग

आमतौर पर फिल्मों की शूटिंग तय शेड्यूल से पीछे चलने या विलंब से होने की खबरें आती हैं। मगर जहां, समय के पाबंद माने जाने वाले हिंदी सिनेमा के खिलाड़ी अभिनेता अक्षय कुमार हो, वहां ऐसी संभावनाएं बहुत कम ही देखने को मिलती है। मुदस्सर अजीज के निर्देशन में बनी अक्षय की आगामी फिल्म खेल खेल में की शूटिंग के दौरान भी अक्षय ने अपना पेशेवर रवैया दिखाया जिससे फिल्म की शूटिंग तय शेड्यूल से पहले ही खत्म हो गई। छह सितंबर को प्रदर्शित हो रही इस फिल्म में अक्षय के साथ वाणी कपूर, तापसी पन्नू, आदित्य सील, फरदीन खान, प्रज्ञा जायसवाल और एमी विर्क जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म के लेकर दैनिक जागरण से बातचीत में आदित्य बताते हैं, 'हमारी फिल्म जयपुर की पृष्ठभूमि पर आधारित है। जैसा कि इस फिल्म का नाम है, वैसे ही हमने खेलते-कूदते हुए इसकी शूटिंग भी की है। फिल्म में सारे कलाकार इतने मंझे हुए और पेशेवर हैं कि हमने फिल्म की शूटिंग बहुत जल्दी खत्म कर ली। मजे की बात यह है कि अक्षय सर ने सेट पर बहुत अच्छा माहौल बना रखा था। सेट पर पूरी मस्ती होती थी, सभी साथ में बैठकर लंच करते थे। यहां तक कि हम शेड्यूल से आगे चल रहे थे, तो हम कभी-कभी सेट पर ही लूडो खेला करते थे।'

संवादों और दृश्यों में अक्षय ने किए कई सुधार: अपने अनुभवों के अनुसार अक्षय कुछ गलत लगने पर फिल्म के संवादों और दृश्यों में सुधार करने में भी पीछे नहीं हटते। आदित्य बताते हैं, 'शूटिंग के दौरान अक्षय सर के अनुभवों से मैं बहुत प्रभावित हुआ। वह सेट पर इंप्रोवाइज (सुधार) करने में इतने माहिर हैं कि उनका कोई जवाब नहीं। वह सिर्फ अपनी पंक्तियां ही नहीं, पूरा सीन इंप्रोवाइज कर देते हैं। उन्होंने मुझे कई बार बताया कि क्या और कैसे करना है।'

अक्षय से पहली मुलाकात: अक्षय से अपनी पहली मुलाकात को लेकर आदित्य बताते हैं, 'अक्षय सर से मेरी पहली फिल्म धड़कन के सेट पर हुई थी। दरअसल मुझे ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट मिला था। मेरी वह तस्वीर एक अखबार में छपी थी। मैंने अक्षय सर को वह तस्वीर दिखाई। उसके बाद अक्षय सर से मुलाकात सीधे इस फिल्म के रिहर्सल के दौरान हुई थी।'

द एम्पायर का दूसरा सीजन बनने की उम्मीद कम

आदित्य ने साल 2021 में प्रदर्शित वेब सीरीज द एम्पायर के दूसरे सीजन को साइन किया था। हालांकि, अब उसके बनने की संभावनाएं कम हैं। वह कहते हैं, 'उस शो को लेकर काफी विवाद हो गया था, इसलिए मुझे नहीं लगता कि फिलहाल इसका दूसरा सीजन बनने की कोई संभावनाएं हैं। मेरे लिए वह शो एक बड़ा मौका था। दरअसल, पहले मुझसे उस शो में बाबर की भूमिका के लिए संपर्क किया गया था, लेकिन तब मैं उसी प्रोडक्शन हाउस के एक अन्य प्रोजेक्ट की शूटिंग में व्यस्त था। फिर निर्माताओं ने मुझे हुमायूं की भूमिका देने का निर्णय लिया। मैंने शो साइन भी उसी चक्कर में किया था कि अगले सीजन में पूरी कहानी हुमायूं के ईर्द-गिर्द होगी।'

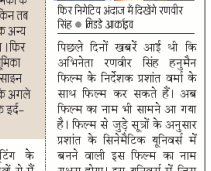

हनुमैन के निर्देशक प्रशांत वर्मा की फिल्म में राक्षस बनेंगे रणवीर

फिर निगेटिव अंदाज में दिखेंगे रणवीर सिंह ● मिडडे आर्काइव

पिछले दिनों खबरें आई थी कि अभिनेता रणवीर सिंह हनुमैन फिल्म के निर्देशक प्रशांत वर्मा के साथ फिल्म कर सकते हैं। अब फिल्म का नाम भी सामने आ गया है। फिल्म से जुड़े सूत्रों के अनुसार प्रशांत के सिनेमैटिक यूनिवर्स में बनने वाली इस फिल्म का नाम राक्षस होगा। इस यूनिवर्स में जिस तरह से प्रशांत अपनी फिल्मों के किरदारों को साथ लाएंगे, उस कल्पना से ही रणवीर काफी प्रभावित हैं। फिल्म की कहानी और पटकथा तैयार है। अब मेकर्स समय का तालमेल बिठाने में लगे हैं, ताकि शूटिंग शुरू की जा सके। हैदराबाद में प्रशांत और रणवीर ने इस फिल्म के लिए हनुमान जयंती के मौके पर एक पूजा भी की थी। राक्षस पीरियड फिल्म होगी, जिसे स्वतंत्रता से पहले के दौर में सेट किया जाएगा। इसकी पृष्ठभूमि पौराणिक होगी। रणवीर के किरदार में निगेटिव शेड्स होंगे। इस फिल्म के अलावा उरीः द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म के निर्देशक आदित्य धर के साथ भी एक फिल्म को लेकर रणवीर की बातचीत चल रही है।

साल भर लग गए श्रीकांत फिल्म के अधिकार लेने में

तुषार निर्देशित श्रीकांत में मुख्य किरदार निभा रहे हैं राजकुमार @tusharhiranandani

निर्देशक तुषार हिरानंदानी को बायोपिक के लिए कहानियों के अधिकार हासिल करने का अच्छा खासा अनुभव हो गया है। सांड की आंख और स्कैम 2003 : द तेलगी स्टोरी के बाद तुषार फिर से बायोपिक फिल्म श्रीकांत - आ रहा है सबकी आंखें खोलने ले आए हैं। यह फिल्म नेत्रहीन उद्योगपति श्रीकांत बोला की जिंदगानी पर बनी है। दैनिक जागरण से बातचीत में तुषार कहते हैं, 'मैं बायोपिक्स इसलिए ज्यादा बनाता हूं, क्योंकि मुझे वह लोग हीरो लगते हैं। दिव्यांगों पर कई कहानियां बनी हैं, लेकिन मुझे श्रीकांत की जिंदगी बहुत प्रेरणादायक लगी। वह खुद को कमजोर या बेचारा नहीं समझते हैं। कई बार मेकर्स ऐसी कहानियों को या तो कामेडी या बहुत ट्रैजिक बना देते हैं। मुझे उन्हें हीरोइक अंदाज में दिखाना था। श्रीकांत से उनकी जिंदगानी पर फिल्म बनाने के अधिकार लेने से लेकर यह फिल्म बनाने तक मुझे पांच साल लगे। पहले उनकी बायोपिक बनाने के राइट्स किसी और के पास थे। वहां से मेरे पास आते-आते ही एक साल लगा। मुझे वास्तविक कहानियों को मसाला फिल्मों के अंदाज में पेश करना पसंद है। श्रीकांत की जिंदगी के अहम मोड़ मैंने फिल्म में जरूर लिए हैं, लेकिन उसके अलावा सब कुछ क्रिएट किया है, क्योंकि इसे डाक्यूमेंट्री नहीं बनानी थी।'

****

एक नजर में

अल्ट्राटेक सीमेंट का शुद्ध लाभ 35 प्रतिशत बढ़ा

नई दिल्ली: अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड ने सोमवार को बताया कि जनवरी-मार्च 2024 तिमाही के दौरान उसका शुद्ध लाभ 2,258.58 करोड़ रुपये रहा है। पिछले वर्ष की समान अवधि के 1,670.10 करोड़ के मुकाबले यह 35.24 प्रतिशत ज्यादा है। आदित्य बिरला समूह की कंपनी ने बताया कि बीती तिमाही में संचालन राजस्व बढ़कर 20,418.94 करोड़ रुपये रहा है। (प्रेट्र)

टाटा मोटर्स और साउथ इंडियन बैंक में समझौता

नई दिल्ली: टाटा मोटर्स ने सोमवार को बताया कि उसने साउथ इंडियन बैंक के साथ एक समझौता किया है। इसके तहत वाणिज्यिक वाहन ग्राहकों और डीलर्स को वित्तीय सुविधा दी जाएगी। टाटा मोटर्स में वाणिज्यिक वाहन कारोबार के वाइस प्रेसिडेंट राजेश कौल ने बताया कि हमारे संचालन में अपने ग्राहकों को वित्तीय समाधान प्रदान करना प्रमुख प्राथमिकता है। (प्रेट्र)

पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को 444 करोड़ का लाभ

नई दिल्ली: वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही यानी जनवरी-मार्च 2024 के दौरान पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को 444 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ है। कंपनी ने बताया कि पिछले वर्ष की समान अवधि के 283 करोड़ रुपये के मुकाबले बीती तिमाही में शुद्ध लाभ में 57 प्रतिशत की वृद्धि रही है। बीती तिमाही में कंपनी की कुल आय 1,806 करोड़ रुपये रही है। (प्रेट्र)

ओला कैब्स के सीईओ ने चार माह में दिया इस्तीफा

नई दिल्ली: कैब सेवाएं देने वाले प्लेटफार्म ओला कैब्स के सीईओ हेमंत बख्शी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सीईओ बनने के चार महीने के भीतर ही यह पद छोड़ दिया है। सूत्रों के अनुसार, कंपनी पुनर्गठन की योजना बना रही है जिससे कम से कम 10 प्रतिशत कर्मचारियों की छंटनी हो सकती है। नया सीईओ चुने जाने तक कंपनी के संस्थापक भाविश अग्रवाल यह जिम्मेदारी संभालेंगे। (आइएएनएस)

बैंकिंग शेयरों में खरीदारी से 941 अंक उछला सेंसेक्स

74,671 के स्तर पर बंद हुआ बीएसई का मानक सूचकांक, निफ्टी भी 223 अंक बढ़कर 22,650 के करीब पहुंचा

मुंबई, प्रेट्र: वैश्विक बाजारों में मजबूती के बीच घरेलू स्तर पर बैंकों और ढांचागत कंपनियों के शेयरों में तगड़ी खरीदारी से सोमवार को बीएसई सेंसेक्स ने 941 अंक की छलांग लगाई। जबकि एनएसई निफ्टी 22,600 के स्तर से ऊपर पहुंच गया। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 941.12 अंक यानी 1.28 प्रतिशत उछलकर 74,671.28 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 990.99 अंक तक बढ़कर 74,721.15 पर पहुंच गया था। नेशनल स्टाक एक्सचेंज (एनएसई) का सूचकांक निफ्टी भी 223.45 अंक यानी एक प्रतिशत बढ़कर 22,643.40 अंक पर बंद हुआ।

सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में से आइसीआइसीआइ बैंक में लगभग पांच प्रतिशत की तेजी रही। मार्च तिमाही में बैंक का शुद्ध लाभ 18.5 प्रतिशत बढ़कर 11,672 करोड़ रुपये हो जाने से इसके शेयरों को रफ्तार मिली। वहीं एचसीएल टेक्नोलाजीज के तिमाही नतीजे निवेशकों का उत्साह जगाने में नाकाम रहे और कंपनी के शेयर करीब छह प्रतिशत गिर गए। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर का कहना है कि अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनियों के बढ़िया तिमाही नतीजों और बांड प्रतिफल में गिरावट आने से घरेलू स्तर पर बाजारों में तगड़ी उछाल देखी गई। बैंक निफ्टी ने चौथी तिमाही में अपने मजबूत प्रदर्शन से बाकी को पीछे छोड़ दिया।

इस तेजी से निवेशकों की संपत्ति में 2.48 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। अब बीएसई में सूचीबद्ध सभी कंपनियों का पूंजीकरण 406.52 लाख करोड़ के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है।

2015 शेयरों में तेजी दर्ज की गई | **1,894** शेयरों में गिरावट आई | **179** शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ

- शुद्ध लाभ बढ़ने से आइसीआइसीआइ बैंक में लगभग पांच प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई
- एचसीएल टेक्नोलाजीज के शेयर छह प्रतिशत गिरे, तिमाही नतीजे उत्साह बढ़ाने में नाकाम रहे

बढ़कर बंद होने वाले शेयर : आइसीआइसीआइ बैंक, इंडसइंड बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, टीसीएस, बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी बैंक

इन शेयरों में दर्ज की गई गिरावट
एचसीएल टेक्नोलाजीज, आइटीसी, विप्रो और बजाज फिनसर्व

सेक्टरवार तेजी

बैंकेक्स	2.70%
वित्तीय सेवाएं	1.81%
यूटिलिटी	1.12%
पावर	0.90%
एनर्जी	0.79%

बाजार ने सप्ताह की शुरुआत मजबूत रुख के साथ की और मौजूदा रुझान को जारी रखते हुए एक प्रतिशत की बढ़त हासिल की है। अनुकूल वैश्विक संकेतों के साथ-साथ बैंकों और ढांचागत कंपनियों के शेयरों में उल्लेखनीय तेजी ने सकारात्मक शुरुआत में मदद की, जो दिन चढ़ने के साथ और मजबूत हुई।
-अजीत मिश्रा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, रेलिगेयर ब्रोकिंग

सोना 130 रुपये गिरा

सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमतें 130 रुपये गिरकर 72,750 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गईं। वहीं चांदी की कीमतें 84,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थिर रहीं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज में कमोडिटी के वरिष्ठ विश्लेषक सौमिल गांधी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कामेक्स पर सोना हाजिर 2,333 डालर पर कारोबार कर रहा था।

सेबी ने बीएसई से कुल मूल्य के आधार पर शुल्क मांगा

नई दिल्ली, प्रेट्र: मार्केटर रेगुलेटर सेबी ने बीएसई को प्रीमियम मूल्य के बजाय उसके विकल्प अनुबंधों के 'कुल मूल्य' के आधार पर शुल्क का भुगतान करने का निर्देश दिया है। इसके बाद शेयर बाजार को अब अधिक रेगुलेटरी शुल्क चुकाना पड़ सकता है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि अनुबंध के कुल मूल्य (नोशनल वैल्यू) तथा प्रीमियम मूल्यों के बीच बड़े अंतर के कारण बीएसई की ओर से सेबी को दिए जाने वाले शुल्क भुगतान में वृद्धि होगी। एक्सचेंज को पिछले वर्षों के अंतर भुगतान को 15 प्रतिशत ब्याज सहित चुकाने को कहा गया है। बीएसई के शुरुआती आंकड़ों से पता चलता है कि एक्सचेंज को 165 करोड़ रुपये के साथ जीएसटी का भुगतान करना पड़ सकता है। सेबी के इस कदम के बाद बीएसई का शेयर सोमवार को एनएसई में 13.31 प्रतिशत तक गिरकर 2,783 रुपये पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय करीब 19 प्रतिशत तक लुढ़क गया था। एक्सचेंज का मार्केट वैल्यूएशन 37,675.24 करोड़ रुपये हैं। विकल्प कारोबार में 'नोशनल' यानी कुल कारोबार किए गए सभी अनुबंधों के कुल खरीद/बिक्री मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि 'प्रीमियम टर्नओवर' कारोबार किए गए सभी अनुबंधों पर भुगतान किए गए 'प्रीमियम' का योग है। चूंकि कुल मूल्य 'प्रीमियम' कारोबार से अधिक है, ऐसे में कुल कारोबार का चयन करने पर ज्यादा शुल्क देना होगा।

4-6 प्रतिशत रह सकती है भारतीय उद्योग के राजस्व में बढ़ोतरी

मुंबई, प्रेट्र: क्रिसिल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023-24 की जनवरी-मार्च तिमाही में भारतीय उद्योग के राजस्व में 4-6 प्रतिशत की वृद्धि रह सकती है। यह सितंबर, 2021 में शुरू हुई कोरोना महामारी की रिकवरी के बाद से सबसे धीमी तिमाही वृद्धि है। यह रिपोर्ट 350 कंपनियों के विश्लेषण पर आधारित है। हालांकि इसमें वित्तीय सेवाओं और तेल और गैस क्षेत्र की कंपनियों का शामिल नहीं किया गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि क्रिसिल द्वारा जिन 47 सेक्टरों पर नजर रखी जाती है, उनमें से केवल 12 में तिमाही के लिए क्रमिक और साल-दर-साल राजस्व वृद्धि में सुधार होने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्वस्थ शहरी मांग के कारण संगठित खुदरा क्षेत्र में लगातार 13वीं तिमाही में वृद्धि दर्ज की गई है। निर्माण से जुड़े क्षेत्रों में राजस्व धीमी गति से बढ़ने की उम्मीद है। जनवरी-मार्च तिमाही के दौरान स्थिर मांग के बावजूद सीमेंट सेक्टर ने मध्यम राजस्व वृद्धि अर्जित की है, क्योंकि अधिक आपूर्ति और तीव्र प्रतिस्पर्धा के चलते कीमतें दबाव में रही हैं।

हिंदुस्तान जिंक के ओएफएस पर फैसला बाजार परीक्षण के बाद

नई दिल्ली, प्रेट्र: खनन सचिव वीएल कांता राव ने सोमवार को कहा कि सरकार बिक्री पेशकश (ओएफएस) के माध्यम से वेदांत समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए प्रतिबद्ध है और इस संबंध में बाजार का परीक्षण करने के बाद कोई फैसला लेगी।

हिंदुस्तान जिंक में सरकार की 29.54 प्रतिशत हिस्सेदारी है। खास बात यह है कि मंत्रालय का बयान हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की डिमर्जर योजना को खारिज करने के बाद आया है। हालांकि राव ने स्पष्ट किया कि एक शेयरधारक के तौर पर कंपनी डिमर्जर पर सहमत नहीं है। कंपनी ने पूंजीकरण को बढ़ाने के लिए अपने कारोबार को जस्ता और चांदी सहित अलग कंपनियों में विभाजित करने की योजना का एलान किया था।

चौथे दौर में दुर्लभ खनिज के 20 ब्लाकों की होगी नीलामी

नई दिल्ली, प्रेट्र : खनन सचिव वीएल कांता राव ने सोमवार को कहा कि जून के अंत में होने वाली चौथे दौर की नीलामी में सरकार दुर्लभ खनिज के करीब 20 ब्लाकों को बिक्री के लिए पेश करेगी। राव ने कहा कि पहले दौर की नीलामी में दुर्लभ खनिज के सात ब्लाकों को बिक्री के लिए पेश किया गया था। इनकी नीलामी की प्रक्रिया पूरी हो गई है और इसके परिणामों की घोषणा एक महीने के अंदर की जाएगी। राव ने एक कार्यक्रम में कहा कि पिछले दो वर्षों के दौरान सरकार ने दुर्लभ खनिजों के खनन को लेकर कई प्रयास किए हैं। इसी का परिणाम है कि दुर्लभ खनिज के 100 से ज्यादा ब्लाक नीलामी के लिए तैयार हैं।

2033 तक ट्रैवल और टूरिज्म क्षेत्र में जुड़ेंगी 5.82 करोड़ नौकरियां

नई दिल्ली, प्रेट्र: वैश्विक टेक्नोलाजी फर्म एनएलबी सर्विसेज का कहना है कि 2033 तक भारत का ट्रैवल और टूरिज्म क्षेत्र 5.82 करोड़ नौकरियां जोड़ने के लिए तैयार है।

एनएलबी सर्विसेज के सीईओ सचिन अलघ का कहना है कि इस क्षेत्र के बढ़ते तालमेल से देश के टियर-1 और टियर-2 शहरों में लगातार रोजगार सृजित हुआ है। कोरोना के दौरान 2020 में पर्यटन क्षेत्र ने 3.9 करोड़ नौकरियां गंवाई जो देश के कुल कार्यबल का आठ प्रतिशत है। महामारी से उबरने के बाद पर्यटन क्षेत्र में सबसे ज्यादा सुधार देखा गया। अगस्त 2023 के दौरान टूरिज्म क्षेत्र में नौकरियों की मांग में 44 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। 2023 में इस क्षेत्र में 16 लाख नौकरियां जुड़ने की उम्मीद है।

बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं से प्रभावित होगा निर्यात

- निर्यातकों के संगठन फियो ने कहा, अगर स्थिति ऐसी ही बनी रही तो इसका असर वैश्विक मांग पर दिखाई पड़ेगा
- भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के अलावा उच्च मुद्रास्फीति और उच्च ब्याज दरें भी मांग में मंदी की प्रमुख वजह

नई दिल्ली, प्रेट्र: निर्यातकों के संगठन फियो ने कहा है कि बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव का असर चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के निर्यात पर पड़ सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के कारण उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितताओं ने 2023-24 में भारत के निर्यात को प्रभावित किया है। यह 3.11 प्रतिशत की गिरावट के साथ 437 अरब डालर पर आ गया है। आयात भी आठ प्रतिशत से अधिक घटकर 677.24 अरब डालर रह गया है।

फियो के महानिदेशक अजय सहाय ने कहा, 'अगर वैश्विक स्थिति ऐसी ही बनी रही तो इसका असर वैश्विक मांग पर दिखाई पड़ेगा। पहली तिमाही में मांग में सुस्ती दिख सकती है।' उन्होंने कहा, 'तमाम चुनौतियों के बावजूद माल ढुलाई की दरों में नरमी आ रही है और यह संकेत देता है कि आने वाले समय में मांग पर असर पड़ सकता है। अगर मौजूदा स्थिति कायम रहती है तो विश्व व्यापार पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।' उन्होंने कहा, 'भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के अलावा उच्च मुद्रास्फीति और उच्च ब्याज दरें भी मांग में मंदी की प्रमुख वजह हैं। यूरोप जैसी कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में और अधिक मंदी देखी जा सकती है।' उन्होंने यह भी कहा कि 2023-24 के दौरान भारत की घरेलू मुद्रा में चीनी युआन के 4.8 प्रतिशत के मुकाबले 1.3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। वहीं रुपये के मुकाबले थाइलैंड की मुद्रा में 6.3 प्रतिशत और मलेशिया की रिंगिट में सात प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

निर्यातकों को लंबी अवधि के लिए धन उपलब्ध कराए सरकार : सहाय

फियो के महानिदेशक ने सरकार को नकदी के मोर्चे पर निर्यातकों के लिए कुछ कदम उठाने का भी सुझाव दिया। सहाय ने कहा, "मांग में कमी के कारण, उसका उठाव कम होगा, इसलिए विदेशी खरीदारों को भुगतान करने में भी लंबा समय लगेगा। ऐसे में हमें लंबी अवधि के लिए धन की जरूरत होगी। उन्होंने निर्यातकों को भी ब्याज सहायता की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने ब्याज समानीकरण योजना को आगे भी जारी रखने की मांग की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आठ दिसंबर, 2023 को इस योजना को 30 जून तक जारी रखने के लिए 2,500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन की मंजूरी दी थी।

एक नजर में

भाजपा सांसद श्रीनिवास प्रसाद का निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक

बेंगलुरु: पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद श्रीनिवास प्रसाद का सोमवार सुबह निधन हो गया। वह बीमारी के कारण कुछ समय से अस्पताल में भर्ती थे। उनके निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने शोक जताया और उन्हें सामाजिक न्याय का चैंपियन करार दिया। वर्ष 1974 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पहली बार चुनाव लड़ने वाले प्रसाद चामराजनगर से छह बार सांसद और मैसुरु जिले के नंजनगुड से दो बार विधायक रहे। (प्रेट्र)

दुष्कर्म पीड़िता की पहचान उजागर की, मप्र कांग्रेस अध्यक्ष व झाबुआ विधायक पर केस

आलीराजपुर: नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की पहचान उजागर करने पर मध्य प्रदेश में आलीराजपुर जिले की पुलिस ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और झाबुआ विधायक विक्रांत भूरिया के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दोनों नेता रविवार को पीड़िता के निवास पर गए थे। स्वजन से चर्चा के दौरान लिया गया चित्र उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किए थे। (नईदुनिया)

भोजशाला सर्वे पर रोक की मांग निरस्त, आठ सप्ताह का और समय दिया गया

इंदौर : मध्य प्रदेश के धार में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला के सर्वे के लिए हाई कोर्ट ने एएसआइ को आठ सप्ताह का और समय दे दिया है। भोजशाला मामले को लेकर हाई कोर्ट में चार अलग-अलग याचिकाओं पर सोमवार को एक साथ सुनवाई हुई। सर्वे पर रोक लगाने के आवेदन को निरस्त करते हुए कोर्ट ने कहा कि वर्तमान स्थिति में इसका कोई मतलब नहीं है। (नईदुनिया)

महादेव एप मामले में अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने मांगा समय

मुंबई: महादेव सट्टेबाजी एप मामले में महाराष्ट्र साइबर विभाग के समक्ष पेश होने के लिए अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने समय मांगा है। अभिनेत्री ने मुंबई में नहीं होने का हवाला दिया है। यह मामला महादेव आनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी एप की सहायक कंपनी फेयरप्ले एप पर 2023 इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) के अनधिकृत प्रसारण से संबंधित है। मामले में गायक व रैपर बादशाह को भी पूछताछ का सामना करना पड़ा था। (एएनआइ)

सत्ता में आए तो जातिवार गणना-आर्थिक सर्वे कराएंगे

राज्य ब्यूरो • पाटण (गुजरात) : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है, तो वह प्राथमिकता के आधार पर पूरे देश में जातिवार गणना और आर्थिक सर्वेक्षण कराएगी। इसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, ओबीसी और सामान्य वर्ग के गरीबों की भागीदारी बढ़ाना है। पाटण में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा और आरएसएस ने चुनाव जीतने पर संविधान बदलने की योजना बनाई है।

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, देश की 90 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों की है। लेकिन आपको कारपोरेट, मीडिया, निजी अस्पतालों, निजी विश्वविद्यालयों या सरकार की नौकरशाही में उनका प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। हम सत्ता में आने के बाद सबसे पहले जातिवार गणना और आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे।

राहुल गांधी ने सत्तारूढ़ भाजपा और आरएसएस पर संविधान को बदलने की योजना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार आरक्षण व्यवस्था के भी खिलाफ है। उन्होंने कहा, भाजपा नेता कह रहे हैं कि वे संविधान को बदल देंगे। हमारा संविधान गरीबों और वंचितों की रक्षा करता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चाहते हैं कि केवल 22-25 लोग सभी संपत्ति, ताकत और प्राकृतिक संसाधनों को नियंत्रित करें। उनके 10 साल के शासन में यही हुआ है।

कांग्रेस सांसद ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ उद्योगपति गौतम अदाणी और अंबानी परिवार पर भी सवाल उठाए। कहा कि जो गुजरात में हुआ आजकल वही देश में हो रहा है। गौतम अदाणी की जिस पर नजर पड़ती है, उसी को उठा लेते हैं। जंगल, जमीन, एयरपोर्ट, बंदरगाह हो या कोई टीवी चैनल सब अपने कब्जे में कर लेते हैं। अदाणी मोदी के मित्र हैं इसलिए उनको यह मिलता है। टीवी पर किसान, दलित, युवा, महंगाई, बेरोजगारी कहीं नजर नहीं आती। बस मोदीजी का चेहरा नजर आता है या फिर नाचता हुआ बालीवुड और अरबपतियों की शादियां नजर आती हैं। बालीवुड नाच रहा है और अदाणी पैसा बना रहे हैं। बताते चलें, कुछ समय पहले मुकेश अंबानी के पुत्र की जामनगर में धूमधाम से प्री-वेडिंग सेरेमनी हुई थी, जिसमें बालीवुड से लेकर हालीवुड के कलाकारों ने प्रस्तुति दी थी।

गुजरात के पाटण में चुनावी जनसभा के दौरान भारतीय संविधान की एक प्रति के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी। • एएनआइ

आदिवासियों को भिखारी बना देगी भाजपा : राहुल

नईदुनिया, बिलासपुर : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की जनसभा में आदिवासी कार्ड खेलते हुए जल, जंगल, जमीन का मुद्दा उठाया। संविधान की रक्षा का संकल्प लेते हुए कहा कि संविधान नहीं रहेगा तो आदिवासी भाइयों को जल, जंगल और जमीन से हाथ धोना पड़ेगा। उनके जीने का तरीका बदल जाएगा। भाजपा के लोग आदिवासियों को वनवासी कहते हैं। आदिवासी इस देश और धरती के पहले मालिक हैं। संविधान बदलने की बात कहने वाले आदिवासियों को जल, जंगल जमीन से बेदखल करना चाहते हैं, आपका अधिकार छीनकर सड़क पर लाना चाहते हैं और भिखारी बनाना चाहते हैं। जो इस देश और धरती के मालिक हैं, उनके साथ इस तरह का बर्ताव हम नहीं होने देंगे। यह चुनाव मुद्दों और विचारधारा पर आधारित है।

मूसेवाला के पिता नहीं लड़ेंगे लोस चुनाव, मनाने में कामयाब हुए बाजवा

जासं, मानसा : दिवंगत गायक सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह लोकसभा चुनाव में आजाद प्रत्याशी के रूप में चुनाव नहीं लड़ेंगे। यह घोषणा नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा और बठिंडा से कांग्रेस प्रत्याशी जीत मोहिंदर सिद्धू ने बलकौर सिंह के साथ बंद कमरे में बैठक के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए की। बलकौर सिंह ने कहा कि बड़े दुख की बात है कि किसी भी पार्टी के किसी भी प्रत्याशी ने इस चुनाव में सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले को मुद्दा बनाना भी जरूरी नहीं समझा। उन्होंने कहा कि इसी कारण मजबूर होकर वे चुनाव लड़ने का फैसला ले रहे थे कि अगर वे अपने बेटे के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर और कौन उठेगा।

उन्होंने कहा कि मेरे बेटे के केस में अभी तक चार्ज फ्रेम नहीं हुए हैं। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मेरे बेटे के हत्यारे लारेंस बिश्नोई को गुजरात ले जाकर सुरक्षित कर देती है। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की तो किसी ने कोई चिंता नहीं की, लेकिन लारेंस को सुरक्षा दी जा रही है। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि सिद्धू मूसेवाला के परिवार की नाराजगी कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं है बल्कि उनकी नाराजगी पंजाब और केंद्र की सरकार के साथ है।

अमित शाह का तंज : आइएनडीआइए जीता तो क्या एक-एक साल के लिए बनेंगे प्रधानमंत्री

- केंद्रीय गृह मंत्री बोले-शरद पवार, लालू, स्टालिन व ममता बनर्जी के बाद क्या बचे समय के लिए राहुल बनेंगे प्रधानमंत्री
- कहा- देश को मजबूर नहीं, मजबूत नेतृत्व चाहिए, नरेन्द्र मोदी का नेतृत्व ही आतंकवाद से बचा सकता है

जागरण टीम • पटना : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को बिहार की चुनावी सभाओं में विपक्षियों के परिवारवाद से लेकर भ्रष्टाचार पर हमला बोला। आइएनडीआइए की हकीकत बताते हुए गृह मंत्री ने कहा कि आइएनडीआइए जीते ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन अगर वे जीतते हैं तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? क्या एक-एक साल के प्रधानमंत्री बनाएंगे। एक साल शरद पवार, एक साल लालू, एक साल स्टालिन, एक साल ममता बनर्जी और जो कुछ समय बचेगा, उसके लिए राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। क्या ऐसा नेतृत्व देश को मजबूत कर सकता है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जीत निश्चित है। उनको तीसरी बार पीएम बनाने का मतलब है बिहार में जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार को खत्म करना और योग्यता के आधार पर राजनीति की शुरुआत करना। शाह सोमवार को मधुबनी जिले के झंझारपुर से एनडीए के जदयू प्रत्याशी रामप्रीत मंडल व बेगूसराय से भाजपा प्रत्याशी गिरिराज सिंह के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। शाह ने कहा कि मोदी का नेतृत्व ही आतंकवाद से बचा सकता है, कश्मीर में शासन व सुशासन स्थापित कर सकता है।

बिहार के मधुबनी में चुनावी सभा को संबोधित करते केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह। • जागरण

कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी है। लालू भी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पिछड़ा वर्ग विरोधी कांग्रेस की गोद में बैठे हैं। मंडल कमीशन के कारण जो आरक्षण मिला, वह 1957 में ही मिल जाता। लेकिन काका साहब कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को कांग्रेस ने रोककर रखा। उसने मंडल कमीशन का विरोध किया। लालू के जीवन का लक्ष्य है बेटे को मुख्यमंत्री बनाना और सोनिया गांधी का राहुल को प्रधानमंत्री बनाना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना में 130 करोड़ टीके लगवाकर भारत को सुरक्षित बनाया। राहुल गांधी इसका मजाक बनाते थे। कहते थे, यह मोदी जी का टीका है। एक दिन अंधेरे में वह भी टीका लगाकर आ गए।

गरीबों की गाढ़ी कमाई डकारने वालों पर होगी कार्रवाई : अमित शाह ने लालू पर हमला करते हुए कहा कि ये घोटालेबाज हैं। कभी चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, नौकरी के बदले जमीन का घोटाला और कई घोटाले किए। मिथिलांचल को भाजपा आधुनिक युग में ले जाना चाहती है और लालू लालटेन युग में। आज बिहार की जनता को बताने आया हूं कि गरीबों की गाढ़ी कमाई का पैसा जिसने भी डकारा है, उस पर कार्रवाई होगी।

बंगाल सरकार निजी व्यक्ति की ओर से कैसे बनी पक्षकार : सुप्रीम कोर्ट

- संदेशखाली मामले में बंगाल सरकार की याचिका पर शीर्ष अदालत ने किया सवाल
- महिलाओं के यौन शोषण और जमीन हड़पने की सीबीआइ जांच का हाई कोर्ट ने दिया था आदेश

जागरण ब्यूरो • नई दिल्ली : संदेशखाली में महिलाओं के यौन शोषण और जमीन हड़पने के मामले की जांच सीबीआइ को सौंपने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची बंगाल सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि राज्य सरकार ने किसी निजी व्यक्ति का हित संरक्षित करने के लिए याचिका क्यों दाखिल की? जब राज्य सरकार के वकील ने कहा कि हाई कोर्ट ने सरकार के खिलाफ टिप्पणियां की हैं, तो शीर्ष अदालत का कहना था कि टिप्पणियां हटवाने के लिए राज्य सरकार हाई कोर्ट जा सकती थी।

हालांकि, बंगाल सरकार के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई जुलाई तक टाल दी, लेकिन स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित रहने को किसी चीज में आधार नहीं बनाया जाएगा। ये टिप्पणियां न्यायमूर्ति बीआर गवई और संदीप मेहता की पीठ ने कलकत्ता हाई कोर्ट के 10 अप्रैल के आदेश के खिलाफ दाखिल बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान सोमवार को कीं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने संदेशखाली में महिलाओं के यौन शोषण और जमीन हड़पने के मामले की सीबीआइ जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले में तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख मुख्य आरोपित है। काफी समय तक फरार रहने के बाद शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया गया था। वह फिलहाल जेल में है।

सोमवार को हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल बंगाल सरकार की याचिका जब सुनवाई पर आई तो पीठ ने सवाल किया कि किसी निजी व्यक्ति का हित संरक्षित करने के लिए राज्य ने याचिका क्यों दाखिल की है। राज्य के वकील जयदीप गुप्ता ने कहा कि हाई कोर्ट ने आदेश में राज्य सरकार के खिलाफ टिप्पणियां की हैं, जबकि राज्य सरकार मामले में पूरी सक्रियता से काम कर रही थी। इसलिए याचिका दाखिल की गई है। इस पर पीठ का कहना था कि अगर टिप्पणियों से शिकायत थी तो राज्य सरकार उन्हें हटवाने के लिए हाई कोर्ट जा सकती थी। तभी बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित करने का अनुरोध करते हुए कहा कि उन्हें कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें पता चली हैं। उस सामग्री को वह दाखिल करना चाहते हैं। यह भी कहा कि हाई कोर्ट के फैसले में जो निष्कर्ष दिए गए हैं, उन्हें चुनौती देने की जरूरत थी। दूसरी ओर सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अनुरोध किया कि कोर्ट आदेश दे कि मामला यहां लंबित रहने को किसी जगह आधार नहीं बनाया जाएगा। इस पर सिंघवी ने कहा कि वह ऐसा कैसे कर सकते हैं। उन्होंने तो विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दाखिल की है। सिंघवी की दलीलों पर पीठ की टिप्पणी थी कि अगर किसी ने हाई कोर्ट के आदेश को आधार बना कर अवमानना याचिका दाखिल की तो राज्य सरकार हाई कोर्ट जाकर कह सकती है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है।

कोर्ट ने कहा कि वह आदेश में स्पष्ट कर रहा है कि मामले की सुनवाई राज्य सरकार के कहने पर स्थगित की जा रही है। इसलिए एसएलपी के लंबित रहने को हाई कोर्ट में सुनवाई लटकाने का आधार नहीं बनाया जा सकता। कोर्ट ने सुनवाई जुलाई तक टालते हुए कहा कि मामले पर सुनवाई का माहौल तभी होगा। पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश सिर्फ जमीन हड़पने के मामले की जांच का ही है। सिंघवी ने कहा कि बहुत सी चीजें कहने को हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 25,753 नौकरियां रद करने का फैसला बहाल रखा

- शिक्षक भर्ती घोटाले में बंगाल के अधिकारियों की भूमिका की सीबीआइ जांच पर रोक

नई दिल्ली • प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले में बंगाल सरकार के अधिकारियों की भूमिका की सीबीआइ जांच कराने संबंधी कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को रद करने पर फिलहाल रोक लगाने से इन्कार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट राज्य संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों में स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) द्वारा की गई 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को रद करने वाले हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने नियुक्तियों को रद करने के हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया। यह देखते हुए कि 25 हजार से अधिक लोगों की नौकरियां छीनना एक गंभीर मामला है, शीर्ष अदालत ने पूछा कि क्या उपलब्ध सामग्री के आधार पर वैध और अवैध नियुक्तियों को अलग करना संभव है? क्या यह पता लगाया जा सकता है कि धोखाधड़ी का लाभ किन लोगों को मिला? पीठ ने कहा, हम उस निर्देश पर रोक लगाएंगे, जिसमें कहा गया है कि सीबीआइ राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ आगे की जांच करेगी।

****